RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2022-2024 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 27 APRIL 2022 TO 03 MAY 2022 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 07 ■ अंक 34 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

चार मई को खुलेगा देश का सबसे बड़ा आईपीओ, प्राइस बैंड 902-949 रुपये प्रति शेयर तय किया गया Page 2

इंदौर की आईटी कंपनी द्वारा स्वच्छ भारत कोष में बहुत बड़ा सहयोग Page 3

प्लेटिनम लव बैंड्स के बेहतरीन और दिलकश डिजाइन Page 7

editoria!

रिकॉर्ड कृषि निर्यात

बीते वित्त वर्ष में हमारे देश ने 400 अरब डॉलर मूल्य का निर्यात कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. इसमें कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा है. वर्ष 2021-22 के वित्त वर्ष में भारत ने 50 अरब डॉलर के कृषि उत्पादों का निर्यात किया है. यह अब तक सर्वाधिक है. इससे पहले सबसे अधिक कृषि निर्यात 2013-14 में हुआ था, जब 43 अरब डॉलर के उत्पाद अन्य देशों को भेजे गये थे. उसके बाद निर्यात में बड़ी कमी आ गयी थी. वर्ष 2016-17 में जब निर्यात 10 अरब डॉलर घट गया, तब वाणिज्य मंत्रालय ने इसके चार मुख्य कारणों को रेखांकित किया था. इनमें पहला कृषि उत्पादन और निर्यात के बीच जुड़ाव का नहीं होना था. राज्य सरकारों और किसानों में निर्यात को ध्यान में रखकर उत्पादन करने को लेकर जागरूकता का अभाव दूसरा कारण था. मंत्रालय ने अपने आकलन में पाया था कि राज्य सरकारें निर्यात को केंद्र सरकार का मामला मानती थीं. इसके अलावा कृषि निर्यात इंफ्रास्ट्रक्चर तथा राज्य सरकारों के पास संबंधित विशेषज्ञता की कमी भी निर्यात घटने की वजहें थीं. इन खामियों को दूर करने के लिए केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने कार्ययोजना बनाकर राज्य सरकारों के साथ-साथ जिला स्तर पर और गांवों में किसानों तक संपर्क स्थापित किया. चूंकि खेती आज भी आजीविका का सबसे बड़ा स्रोत है, इसलिए किसानों की आय बढ़ाना और कृषि क्षेत्र का विकास करना आवश्यक है. यह सरकार की प्राथमिकताओं में भी है. वाणिज्य मंत्रालय ने किसानों को अधिशेष उत्पादन के निर्यात का भरोसा दिलाया. इन प्रयासों का परिणाम अब हमारे सामने है. कोरोना महामारी से उत्पन्न हुई समस्याओं और बाधाओं के बावजूद कृषि निर्यात में बढ़ोतरी उत्साहजनक है. वैश्विक स्तर पर एक ओर जहां खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर ढुलाई में मुश्किलें भी हैं. लॉकडाउन और अन्य पाबंदियों से भी निर्यात प्रक्रिया प्रभावित हुई है. ऐसी मुश्किलों को दूर करने के लिए देश के भीतर और बाहर वाणिज्य मंत्रालय सक्रिय रहा. निर्यात बढ़ने का एक उल्लेखनीय कारक नये बाजारों की तलाश तथा मौजूदा बाजारों में ज्यादा कारोबार भी रहे. हमारे देश में कई तरह के कृषि उत्पाद हैं और सभी के निर्यात को प्रोत्साहित करने से ही निर्यात में वृद्धि को बरकरार रखा जा सकता है. इस संबंध में हो रही प्रगति संतोषजनक है. पिछले वित्त वर्ष में 10 अरब डॉलर मूल्य के चावल का निर्यात हुआ है. चावल के वैश्विक निर्यात में अब भारत की हिस्सेदारी 50 फीसदी है. इस बार सामुद्रिक उत्पादों का निर्यात भी आठ अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है. अन्य प्रमुख उत्पादों में चीनी, गेहूं, कॉफी, मांस, पॉल्ट्री, दुग्ध, मसाले, कपास आदि हैं. रूस-यूक्रेन युद्ध से वैश्विक खाद्य आपूर्ति बड़े पैमाने पर बाधित हुई है. ऐसे में भारत एक महत्वपूर्ण निर्यातक के रूप में उभर रहा है और हमारे खाद्यान्न के लिए नये बाजार मिल रहे हैं. ऐसे में कृषि निर्यात में बढ़त बनी रहेगी.

अगले पांच महीनों में दोगुनी हो सकती हैं ईंधन की कीमतें

अर्थशास्त्री ने दी चेतावनी, आम आदमी का होगा बुरा हाल

नई दिल्ली। एजेंसी

कच्चे तेल की उच्च कीमतों के चलते पिछले दिनों हमने पेट्रोल-डीजल और गैस की कीमतों में भारी उछाल देखा है। ईंधन की कीमतों में इस बढ़ोतरी ने आम आदमी को काफी प्रभावित किया है। ईंधन की उच्च कीमतों से अन्य कई वस्तुओं में भी महंगाई देखने को मिली है। वहीं, विश्लेषक ईंधन की कीमतों के बारे में डराने वाले अनुमान लगा रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, अगर गैस व तेल की कीमतों में वृद्धि जारी रहती है, तो शरद ऋतु तक ईंधन की कीमतें दोगुनी हो सकती हैं। शरद ऋतु 15 सितम्बर से 15 दिसम्बर तक होती है। अर्थशास्त्री क्रिस जॉन्स ने कहा कि यह वृद्धि उपभोक्ताओं के लिए 'विनाशकारी' होगी। जॉन्स ने कहा कि कीमतों में वृद्धि का अकेला कारण यूक्रेन पर रूस का आक्रमण नहीं है। उन्होंने एक पॉडकास्ट में बताया, 'यह पुराने जमाने का अर्थशास्त्र है, यह दुनिया भर के कुछ प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों में और कुछ प्रमुख वस्तुओं में आपूर्ति से अधिक मांग है।'

गैस की आपूर्ति में व्यवधान एक बड़ी समस्या

जॉन्स ने आगे कहा कि गैस की आपूर्ति में व्यवधान एक बड़ी समस्या है, क्योंकि पुतिन पिछले कुछ समय से गैस की आपूर्ति के साथ गेम खेल रहे हैं। उन्होंने कहा, 'मौसम की घटनाओं का एक संयोजन

भी इसके पीछे है। कुछ साल पहले काफी अधिक ठंडी सर्दी पड़ी थी, जिसके कारण गैस भंडार समाप्त हो गए थे। इसके बाद गर्मियों के दौरान जर्मनी जैसे देशों में गैस टैंकों को उतना नहीं भरा गया जितना भरा जाना चाहिए।'

आपूर्ति से अधिक है मांग

अर्थशास्त्री जॉन्स ने कहा कि मांग आपूर्ति से अधिक हो गई है और इसके चलते काफी समय से गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा, 'हम यूके की बात करें, तो वहां अजीबोगरीब तरीके से चीजों को करते हैं। उन्हें इस समय उपभोक्ताओं के लिए गैस और बिजली की कीमतें साल में केवल दो बार बदलने की अनुमति है। यूके में कीमतों में वृद्धि जो अभी लागू की गई है, 50 से 100 फीसद तक है। इसलिए पिछले कुछ हफ्तों में कुछ बिल दोगुने हो गए हैं।

छह महीने बाद दोगुनी हो जाएंगी कीमतें

उन्होंने कहा, 'अगर अगले छह महीनों के लिए गैस और तेल जैसी चीजों की मौजूदा कीमतें बनी रहती हैं, तो ब्रिटेन और यूरोप के आसपास की अन्य जगहों पर या कम से कम आयरलैंड में शरद ऋतु में शायद फिर से कीमतें लगभग दोगुनी हो जाएंगी।'

रूस ने आपूर्ति रोकी तो आसमान पर होंगी कीमतें

जॉन्स ने कहा कि आयरलैंड यूके पाइपलाइनों के माध्यम से उत्तरी सागर से गैस का आयात करता है। अगर रूस अपनी गैस आपूर्ति रोक देता है, तो उस गैस के लिए प्रतिस्पर्धा 'बेहद' बढ़ जाएगी। अगर रूस यूरोप को व विशेष रूप से जर्मनी को उत्तरी सागर में उत्पादित होने वाली गैस की आपूर्ति रोक देता है, तो कीमतों में बहुत वृद्धि होगी।' दूसरी बात यह है कि जब यूरोप को गैस की रूसी आपूर्ति बंद कर दी जाएगी, तो उस गैस के लिए प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ जाएगी।'

वेस्ट प्लास्टिक के उपयोग से बनी सड़कें सस्ती होने के साथ ही टिकाउ भी

भोपाल। एजेंसी

शहरी क्या ग्रामीण क्षेत्र में भी लगातार सड़कों का टूटना आमजन के लिए परेशानी का विषय बना रहता है। ऐसे में लगातार उन्हें (शहरी व ग्रामीण) दूरुस्त करने के लिए जहां एक ओर राज्य को अच्छा पैसा खर्च करना पड़ता है। वहीं इसके बावजूद ये कितने समय तक टिक पाएंगी कहा नहीं जा सकता। ऐसे में मध्यप्रदेश में ग्रामीण सड़कें बनाने के करीब 18 तरह के नए प्रयोग किए गए हैं। इनसे निर्माण लागत तो कम आई ही साथ ही इनमें टिकाऊपन भी देखने को मिला। वहीं सबसे ज्यादा सड़कें वेस्ट प्लास्टिक का उपयोग कर बनाई गई हैं। इससे सड़कों के निर्माण की लागत में दस फीसदी से अधिक की कमी आई है। देश में सबसे ज्यादा प्लास्टिक की सड़कें बनाई गई हैं, जिसके लिए मप्र को अवार्ड भी मिला है। प्रदेश (श्इ) में 11 हजार किमी से ज्यादा सड़कें कई नवाचार से बनाई गई हैं। यह नवाचार रसायन और मटेरियल की उपलब्धता के साथ-साथ क्षेत्र की जीयोग्राफिकल वातावरण के आधार पर किए गए हैं। प्रत्येक नवाचार में पांच से दस फीसदी लागत राशि को कम किया गया है। निर्माण के लिए फैक्ट्रियां अपना वेस्ट रासायनिक मटेरियल उपलब्ध कराती हैं, ताकि डामर, सीमेंट का उपयोग कम हो। घनी ग्रामीण बस्तियों में कई जगह पर पैनल्ड कांक्रीट की सड़कें बनाई गई हैं। जहां सड़कें खराब हो जाती हैं, वहां उतने पैनल को निकालकर दूसरा पैनल लगा दिया जाता है। रख-रखाव की लागत 70 फीसदी कम हो जाती है।

सोपा का सरकार से आग्रह, जीएम सोयाबीन मील के आयात की इजाजत न दी जाए

नयी दिल्ली। एजेंसी

सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सोपा) ने सरकार से आनुवांशिक रूप से संशोधित सोयाबीन मील के आयात की अनुमति नहीं देने का आग्रह किया है। सोपा ने बुधवार को कहा कि ऐसा करने से किसानों और स्थानीय प्रसंस्करण करने वालों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सोपा के अध्यक्ष दावीश जैन ने एक पत्र में कहा, ''भारत में सोयाबीन मील की उच्च कीमतों का हवाला देते हुए पॉल्ट्री उद्योग ने एक बार फिर सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें जीएम (आनुवांशिक रूप से संशोधित) सोयाबीन मील आयात करने की अनुमति दी जाए।'' उन्होंने कहा, ''कुछ व्यापारियों और पॉल्ट्री उद्योग द्वारा जीएम सोयाबीन मील के आयात का सुझाव पूरी तरह से प्रतिकूल होगा।'' उन्होंने पशुपालन सचिव अतुल चतुर्वेदी को लिखे पत्र में आरोप लगाया कि पॉल्ट्री उद्योग 90 लाख टन सोयाबीन मील की मांग करता है, जो पूरी तरह गलत है और तथ्यों द्वारा समर्थित नहीं है। जैन ने कहा कि आयात के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए इस बढ़ी हुई मांग का दावा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में सोयाबीन मील के आयात का कोई औचित्य नहीं है। सोयाबीन और सोयाबीन मील की ऊंची कीमतें एक वास्तविकता है, जिसे स्वीकार करना चाहिए।

चार मई को खुलेगा देश का सबसे बड़ा आईपीओ, प्राइस बैंड 902-949 रुपये प्रति शेयर तय किया गया

नई दिल्ली। एजेंसी

देश के सबसे बड़े आईपीओ का इंतजार कर रहे निवेशकों के लिए बड़ी खबर है। दीपम की ओर से इसे लॉन्च करने को लेकर आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव तुहिन कांत पांडे ने बुधवार को इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश की सबसे बड़ी कंपनी एलआईसी का आईपीओ चार मई को खुलेगा और नौ मई को बंद होगा। इसके अलावा ये बाजार में 17 मई को लिस्ट हो सकता है।

दीपम सचिव ने किया एलान

तुहिन कांत पांडे ने बताया कि एलआईसी आईपीओ के लिए प्रति शेयर 902 रुपये से 949 रुपये पर प्राइस बैंड निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि हम इसे एलआईसी 3.0 चरण कहेंगे। गौरतलब है कि एलआईसी की इस आईपीओ के लिए करीब 21,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है। इसके जरिए सरकार एलआईसी में अपनी 3.5 फीसदी हिस्सेदारी बेच रही है। यहां बता दें कि पहले इसका आकार 65 हजार करोड़ रुपये रखने का निर्णय किया गया था, जिसे अब बदल दिया गया है।

एंकर निवेशकों के लिए दो मई को खुलेगा

दीपम सचिव ने आईपीओ को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि एलआईसी के आईपीओ से सरकार 20,557 करोड़ रुपये जुटाएगी। सब्सक्रिप्शन के लिए यह इश्यू 9 मई 2022 तक खुला रहेगा। आईपीओ 22.13 करोड़ शेयरों की बिक्री के लिए एक शुद्ध

पेशकश होगी। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए कहा कि एंकर निवेशकों के लिए यह मेगा आईपीओ दो मई को खोल दिया जाएगा।

कर्मचारियों-पॉलिसीधारों को इतनी छूट

उन्होंने कहा कि पहले सामने आए भू-राजनैतिक हालातों के लगे अस्थायी झटकों से अब बाजार उबर गया है। पांडे ने कहा कि रिटेल निवेशकों और कर्मचारियों समेत एलआईसी पॉलिसीधारकों के लिए छूट का प्रावधान किया गया है। आईपीओ में रिटेल निवेशकों और पात्र कर्मचारियों को 45 रुपये प्रति शेयर की छूट मिलेगी, जबकि पॉलिसीधारकों को 60 रुपये प्रति शेयर की छूट दिए जाने का फैसला किया गया है। इश्यू के लिए बिड लॉट 15 तय किया गया है।

पूरी तरह ऑफर फॉर सेल

तुहिन कांत पांडे ने कहा कि कैपिटल मार्केट के प्रतिकूल हालात के मद्देनजर एलआईसी आईपीओ का आकार बिल्कुल सही है। इससे कैपिटल की कमी नहीं होगी और मॉनेटरी सप्लाई भी बाधित नहीं होगी। गौरतलब है कि एलआईसी आईपीओ पूरी तरह से ऑफर ऑन सेल होगा। कंपनी इसके जरिए एंकर निवेशकों के लिए 5.929 करोड़ शेयर जारी करेगी। कर्मचारियों के लिए 15.8 करोड़ शेयर और पॉलिसीधारकों के लिए 2.214 करोड़ शेयर रिजर्व रखे गए हैं। इसके अलावा क्यूआईबी के लिए 9.883 शेयर निर्धारित किए गए हैं।

पहले सरकार की ये थी योजना

बता दें कि एलआईसी आईपीओ को लेकर पहले सरकार की योजना पांच फीसदी हिस्सेदारी बेचने की थी। इसके तहत कंपनी 31.6 करोड़ शेयर जारी करने वाली थी। लेकिन रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण बाजार में आई उथल-पुथल के मद्देनजर इसका आकार छोटा कर दिया गया। आपको बता दें कि भले ही सरकार ने आईपीओ का आकार 65 हजार करोड़ रुपये से घटाकर 21 हजार करोड़ रुपये कर दिया है, लेकिन फिर भी ये सबसे बड़ा आईपीओ होगा।

एलआईसी में सरकार की 100% हिस्सेदारी

गौरतलब है कि देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में सरकार की 100 फीसदी हिस्सेदारी है। यानी सरकार के पास कंपनी के 632.49 करोड़ शेयर हैं। यहां बता दें कि इससे पहले कंपनी ने जो योजना बनाई थी, उसके मुताबिक, पॉलिसीधारकों के लिए आईपीओ के इश्यू साइज में 10 फीसदी, जबकि कर्मचारियों के लिए पांच फीसदी का हिस्सा निर्धारित किया गया था।

अनुमानः इस महीने रिकॉर्ड तोड़ सकता है जीएसटी संग्रह 1.45 से 1.50 लाख करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद

मुंबई। एजेंसी

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह इस महीने रिकॉर्ड तोड़ सकता है। उम्मीद है कि 1.45 से 1.50 लाख करोड़ रुपये इसके जरिये सरकार को मिल सकता है। मार्च में अब तक का सबसे ज्यादा 1.42 लाख करोड़ रुपये का टैक्स मिला था। अप्रैल 2021 में सरकार को 1.41 लाख करोड़ रुपये मिले थे, जो दूसार सबसे बड़ा रिकॉर्ड था। वित्त मंत्रालय के हवाले से कहा गया है कि मासिक आधार पर इस बार ज्यादा ई-वे बिल बने हैं, जिनके कारण टैक्स में बढ़ोतरी होगी। अगर अप्रैल में 1.45 लाख करोड़ रुपये सरकार को मिलते हैं तो यह लगातार दसवां महीना होगा, जिसमें एक लाख करोड़ से ज्यादा का टैक्स मिलेगा।

जुलाई से मिल रहा है हर महीने 1 लाख करोड़ से ज्यादा टैक्स

जुलाई, 2021 से लेकर अब तक हर महीने एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का टैक्स मिला है। मासिक आधार पर सबसे ज्यादा बढ़त 33 फीसदी जुलाई महीने में ही हुई थी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में जीएसटी के तहत कुल 14.83 लाख करोड़ रुपये मिले थे। यह 2020-21 में मिले 11.37 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 30 फीसदी ज्यादा था। माना जा रहा है कि अर्थव्यवस्था में सुधार और चोरी पर लगाम लगने की वजह से टैक्स वसूली में बढ़त हो रही है। वित्त मंत्रालय ने 25 अप्रैल को कहा था कि मंत्रियों का एक समूह टैक्स की दरों को लेकर अभी भी रिपोर्ट नहीं सौंपा है। पिछले साल इस समूह को बनाया गया था। इसके मुताबिक, टैक्स की दरों में संशोधन किया जाना है।

सरकार अप्रैल-सितंबर में फॉस्फेट, पोटाश उर्वरकों के लिए 60,939 करोड़ रुपये की सब्सिडी देगी

नयी दिल्ली। एजेंसी

सरकार ने बुधवार को चालू वित्त वर्ष के पहले छह महीनों में डीएपी सहित फॉस्फेट और पोटाश (पीएंडके) उर्वरकों के लिए 60,939.23 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी। किसानों को उचित कीमत पर खाद उपलब्ध कराने के लिये यह फैसला किया गया है। आधिकारिक बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में खरीफ सत्र (एक अप्रैल, 2022 से 30 सितंबर, 2022 तक) में फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों के लिये पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरों को मंजूरी दी गयी। इसमें कहा गया है, ''मंत्रिमंडल ने खरीफ सत्र 2022 के लिये 60,939.23 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी है। इसमें माल ढुलाई सब्सिडी के माध्यम से स्वदेशी उर्वरक (एसएसपी) के लिये समर्थन और डीएपी को देश में बनाने तथा आयात को लेकर अतिरिक्त सहायता शामिल है।'' डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) और उसके कच्चे माल के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि हुई है लेकिन सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि किसानों पर बोझ न बढ़े। बयान के अनुसार, ''केंद्र सरकार ने डीएपी पर सब्सिडी बढ़ाकर 2,501 रुपये प्रति बोरी कर दी है जो अबतक 1,650 रुपये प्रति बोरी थी। यह पिछले साल की सब्सिडी दर से 50 प्रतिशत अधिक है।'' मंत्रिमंडल की बैठक के बाद फैसले के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले पूरे वित्त वर्ष में इन पोषक तत्वों पर लगभग 57,150 करोड़ रुपये की सब्सिडी के मुकाबले सिर्फ खरीफ सत्र के लिये पीएंडके उर्वरकों पर 60,939 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि डीएपी पर सब्सिडी बढ़ाकर 2,501 रुपये प्रति बोरी कर दी गई है और किसानों को 1,350 रुपये प्रति बोरी की दर से डीएपी मिलती रहेगी। ठाकुर ने कहा कि डीएपी पर सब्सिडी 2020-21 में 512 रुपये प्रति बैग से बढ़ाकर 2,501 प्रति बैग कर दी गई है। वैश्विक बाजारों में उर्वरकों की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है, लेकिन सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि किसानों पर बोझ न बढ़े। पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) योजना अप्रैल, 2010 से लागू की जा रही है। एनबीएस नीति के तहत सरकार वार्षिक आधार पर नाइट्रोजन (एन), फॉस्फेट (पी), पोटाश (के) और सल्फर (एस) जैसे पोषक तत्वों पर सब्सिडी की दर तय करती है।

क्रूड को लेकर अमेरिकी दबाव का असर नहीं RIL ने रूस से खरीदा 1.5 करोड़ बैरल तेल

कच्चे तेल को लेकर अमेरिका और यूरोपियन देशों के दबाव का भारत पर कोई असर नहीं दिख रहा है। सरकारी तेल कंपनियों के साथ साथ निजी क्षेत्र ने भी रूस से कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ा दी है, यह इस लिए भी अहम है कि रूस यूक्रेन संकटके बाद आईटी सेक्टर सहित कुछ अन्य क्षेत्र की निजी कंपनियां पश्चिमी देशों पर कारोबारी निर्भरता की वजह से रूस में अपना कारोबार बंद कर रही हैं। रॉयटर्स की एक खबर के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बड़ी मात्रा में रूस से कच्चा तेल खरीदने का समझौता किया है। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय कंपनियां रूस से तेल खरीद इसलिये बढ़ा रही हैं क्योंकि उन्हें कच्चा तेल बेहद सस्ती दरों पर और आसान शर्तों के साथ मिल रहा है।

RIL ने बढ़ाई खरीद

रॉयटर्स ने तेल कारोबारियों के हवाले से जानकारी दी है कि दुनिया के सबसे बड़े तेल रिफायनिंग कॉम्प्लैक्स को चलाने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रूस यूक्रेन संकट के दौरान रूस से 1.5 करोड़ बैरल तेल की खरीद का सौदा किया है। सूत्रों के मुताबिक डिलीवरी के हिसाब से कंपनी ने जून तिमाही में यानि अप्रैल, मई, और जून के लिये 50 लाख बैरल प्रतिमाह के औसत से तेल की खरीद की है। रॉयटर्स के मुताबिक संकट से पहले रिलायंस शायद ही कभी रूस से तेल खरीदता था, क्योंकि भारत से दूरी की वजह से उसकी सप्लाई काफी महंगी पड़ती थी। हालांकि पश्चिमी देशों के द्वारा प्रतिबंध लगाने के साथ रूस के कारोबारी आसान शर्तों और ऊंची छूट के साथ तेल ऑफर कर रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार 5 अप्रैल से 9 मई के बीच रिलायंस को कुल 80 लाख बैरल क्रूड की सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट है। कारोबारियों के मुताबिक रिलायंस को कीमतों में छूट के साथ डिलीवरी की आसान शर्तें ऑफर की गई हैं। रिलायंस की जामनगर रिफायनरी 14 लाख बैरल तेल प्रति दिन प्रोसेस करती है। रिलायंस द्वारा खरीदी गई मात्रा उसकी 10 दिन की रिफानिंग क्षमता के बराबर है और देश की 3 दिन की मांग के बराबर है।

भारत ने बढ़ाई तेल की खरीद

रूस यूक्रेन संकट पर भारत ने अभी तक सतर्क रुख अपनाया है और वो किसी का पक्ष नहीं ले रहा है। हालांकि देश की जरूरतों को पूरा करने के लिये भारत रूस से कच्चे तेल का कारोबार लगातार बढ़ा रहा है। रॉयटर्स के आंकड़ों की माने तो रूस यूक्रेन संकट शुरू होने के बाद से अब तक भारत रूस से इतना तेल खरीद चुका है जितना पूरे 2021 में खरीदा गया था। बीपीसीएल ने मई के लिये 20 लाख बैरल, एचपीसीएल ने 20 लाख बैरल और इंडियन ऑयल ने 60 लाख बैरल की खरीद की है। इसके साथ ही इंडियन ऑयल का साल 2022 के लिये रोजनेफ्ट के साथ 1.5 करोड़ बैरल की सप्लाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट है। रॉयटर्स पहले ही जानकारी दे चुका है कि रूस भारत को 25 से 30 डॉलर प्रति बैरल की छूट ऑफर कर रहा है। इसके साथ ही डिलीवरी पर भी छूट ऑफर हो रही है। भारत अपनी जरूरत का 80-85 प्रतिशत कच्चा तेल बाहर से मंगाता है। अब तक इस आयात में रूस की हिस्सेदारी बेहद कम थी। हालांकि इस साल इसमें बढ़त दर्ज होना तय है।

पाम तेल पर प्रतिबंध : शैंपू-साबुन से चॉकलेट तक के बढ़ सकते हैं दाम, इंडोनेशिया 28 अप्रैल से निर्यात पर लगाएगा पाबंदी

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

देश में खाद्य तेल की आसमान छूती कीमतों के बीच इंडोनेशिया 28 अप्रैल से पाम तेल का निर्यात बंद कर रहा है। इस फैसले का सबसे ज्यादा असर भारत पर होगा क्योंकि हम अपनी कुल जरूरतों का आधा से अधिक पाम तेल इंडोनेशिया से खरीदते हैं। पाम तेल महंगा होने से न सिर्फ खाने के तेल महंगे हो जाएंगे बल्कि शैंपू-साबुन से लेकर केक, बिस्कुट और चॉकलेट तक के दाम बढ़ जाएंगे। विशेषज्ञों ने कहा, कई तेलों में तो पाम तेल मिलाया जाता है क्योंकि इसमें महक नहीं होती है। एफएमसीजी एवं सौंदर्य प्रसाधन बनाने वाली कंपनियां भी बड़ी मात्रा में पाम तेल का इस्तेमाल करती हैं। भारत करीब 90 लाख टन पाम तेल खरीदता है। इसमें 70 फीसदी पाम तेल का आयात इंडोनेशिया से होता है। इंडोनेशिया से पाम तेल का निर्यात बंद होने के बाद मलयेशिया पर निर्भरता बढ़ेगी और खाद्य तेल के दाम 20 फीसदी तक बढ़ सकते हैं।

देश में आठ फीसदी तक बढ़ सकते हैं खाद्य तेल के दाम, यहां होता है पाम तेल का इस्तेमाल

पाम तेल पूरी दुनिया में सबसे लोकप्रिय वनस्पति तेल है। दुनियाभर के करीब 50 फीसदी घरेलू उत्पादों में इसका इस्तेमाल होता है। पाम तेल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल खाने के तेल की तरह होता है। शैंपू, नहाने के साबुन, टूथपेस्ट, विटामिन की गोलियां, सौंदर्य प्रसाधन उत्पाद, केक और चॉकलेट आदि में भी इसका इस्तेमाल होता है।

इन कंपनियों पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर

हिंदुस्तान यूनीलिवर : कंपनी ने 2016 में बताया था कि वह हर साल 10 लाख टन कच्चे पाम तेल का इस्तेमाल उत्पादों में करती है। कंपनी साबुन, शैंपू, क्रीम, फेसवॉश सहित दर्जनों कॉस्मेटिक उत्पाद बनाती है।

नेस्ले : किटकैट चॉकलेट बनाने वाली कंपनी ने 2020 में 4.53 लाख टन पाम तेल खरीदा था। इसमें अधिकतर इंडोनेशिया से खरीदे गए, जबकि कुछ मलयेशिया से आयात हुआ था।

प्रॉक्टर एंड गैंबल : कंपनी ने 2020-21 में 6.05 लाख टन पाम तेल खरीदा था। ज्यादतर का इस्तेमाल होम केयर एवं सौंदर्य प्रसाधन के उत्पाद बनाने में किया गया।

मॉन्डलेज इंटरनेशनल : ओरियो बिस्कुट बनाने वाली कंपनी भी अपने उत्पादों में इस्तेमाल करने के लिए भारी मात्रा में पाम तेल खरीदती है।

लॉरियल : कंपनी अपने उत्पादों में पाम तेल का इस्तेमाल करती है। इसने 2021 में अपने उत्पादों में 310 टन पाम तेल का इस्तेमाल किया।

इंडोनेशिया से जल्द बातचीत करे सरकार : एसईए

खाद्य तेल उद्योग के संगठन साल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन (एसईए) ऑफ इंडिया ने इंडोनेशिया के प्रस्तावित पाम तेल निर्यात पर पाबंदी को लेकर सरकार के स्तर पर तुरंत बातचीत का सुझाव दिया है। एसईए के महानिदेशक बीवी मेहता ने कहा कि इंडोनेशिया के फैसले का हमारे घरेलू बाजार पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि पाम तेल के कुल आयात का आधा हिस्सा वहां से आयात होता है। इस कमी को कोई भी पूरा नहीं कर सकता है। इसलिए इस मामले को लेकर हम केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के संपर्क में हैं। इस समय खाना बनाने में उपयोग होने वाले तेल के दाम इंडोनेशिया के घरेलू बाजार में करीब 40 से 50 फीसदी बढ़ गए हैं। खाद्य तेल रिफाइनरी कंपनी के एक अधिकारी ने कहा कि यूक्रेन युद्ध से सूरजमुखी और सोयाबीन तेल पर पहले से दबाव है। अगर इंडोनेशियाई तेल पर पाबंदी से जल्दी नहीं निपटा गया तो इसका व्यापक प्रतिकूल असर पड़ेगा।

इंदौर से निकला चायवाला बना ग्लोबल फ्रेंचाइज का मालिक

सऊदी से कनाडा तक चल रही चाय फ्रेंचाइजी की बिक्री

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

सेन्ट्रल इंडिया का पहला चाय-कैफे फ्रेंचाइज ब्रांड, द टी फैक्ट्री, जल्द ही गल्फ देशों समेत कनाडा में भी अपनी नई फ्रेंचाइज की शुरुआत करने जा रहा है. इंदौर से शुरू हुआ द टी फैक्ट्री का कारोबार, देशभर में 161 से अधिक फ्रेंचाइज संचालित करने वाला फूड एवं बेवरेज इंडस्ट्री का एकमात्र चाय कैफे है. 2013 में लोगों को इस नए कांसेप्ट से मिलाने वाले शशांक शर्मा, महज 22 साल की उम्र में, परंपरा के खिलाफ, अपने बिज़नेस आईडिया को लेकर मार्केट में उतरे थे. उस दौर में प्रमोशन का एकमात्र जरिया, सोशल मीडिया बेहद खर्चीला हुआ करता था, चूंकि इंटरनेट की कीमतें आम आदमी के बजट से बाहर हुआ करती थी, मसलन डिजिटल प्रमोशन के जरिये लोगों तक पहुंचने की संभावनाएं आज के मुकाबले न के बराबर हुआ करती थी। चर्चा के दौरान शशांक ने कहा कि मेरा लक्ष्य चाय लवर्स को एक ही जगह पर कश्मीरी कावा, ग्रीन टी, मसाला टी, जिंजर टी जैसे विभिन्न क्षेत्रों की चाय का स्वाद देना था और चाय को एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस बनाने के लिए यूनिक आइडियाज पर काम करता था। टी-फैक्ट्री चाय फ्रेंचाइज फाउंडर शशांक शर्मा ने कहा कि, शुरुआत में लोग इसे नॉन प्रॉफिटेबल आईडिया समझते थे और सोशल मोटिवेशन की भारी कमी झेलती पड़ती थी. शुरुआती दौर की सबसे बड़ी चुनौती आईडिया को लोगों तक पहुंचाने था। सोशल मीडिया पर क्रांति अभी पिछले कुछ सालों में शुरू हुई है, लेकिन तब एक ऐंड्रॉयड फोन भी महंगा था और इंटरनेट की कीमतें भी बड़ा बजट मांगती थी। डिजिटलीकरण पर काम करते हुए हम वर्तमान में देश के आधे से अधिक हिस्से में अपनी फ्रेंचाइजी का संचलन किया जा रह है। लोकल प्रतिस्पर्धा के सवाल पर उन्होंने कहा, एक चाय कैफे फ्रेंचाइजी के रूप में हम देश के अपने पहले चाय कैफे कांसेप्ट को लोकल ब्रांड से नेशनल और फिर इंटरनेशनल बनाने में सफल रहे हैं। हम प्रतिस्पर्धा नहीं मार्गदर्शन देने में काम कर रहे हैं। वर्तमान में दुनियाभर में द टी फैक्ट्री की 161 से अधिक चाय फ्रेंचाइजी आउटलेट्स संचालित हो रही हैं, जिनमें देश के अंदर जम्मू, बैंगलोर, हरिद्वार, होशंगाबाद, भरूच, मोहाली, अहमदाबाद, मथुरा, इंदौर और बीकानेर जैसे शहरों में द टी फैक्ट्री फ्रेंचाइजी सफल संचालन जारी है। वहीं पड़ोसी देश नेपाल समेत सऊदी, शारजहां जैसे गल्फ देशों में भी शशांक की चाय का बोल बाला है।

निवेश का आमंत्रण: अमेरिकी सेमीकंडक्टर को भारत में मिलेगा प्रोत्साहन

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने की उद्योग जगत से मुलाकात

वशिंगटन। एजेंसी

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिकी सेमीकंडक्टर उद्योग के अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें भारत में निवेश का आमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए कंपनियों को प्रोत्साहन का फायदा दिया जाएगा। सिलिकॉन वैली में स्थित कंपनियों के अधिकारियों को उन्होंने भारत में तमाम अवसरों की जानकारी दी और कहा कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत सरकार एक बड़े मिशन को लेकर चल रही है। सरकार ने पिछले साल देश में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 76,000 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी थी। इस योजना का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर भारत को उच्च प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादन के प्रमुख के रूप में स्थापित करना है।

चिप उद्योग को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन नीति : भारत चिप उद्योग को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन की नीति को बढ़ावा दे रहा है। वित्तमंत्री ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र की दिग्गज हस्तियों के साथ बैठक में कहा कि भारत ने हाल के समय में अपनी क्षमताओं को काफी हद तक बढ़ाया है। रिसर्च एवं विकास के लिए अकादमिक संस्थानों के साथ सहयोग भी कर रहे हैं। वित्तमंत्रालय ने इस बारे में एक ट्वीट किया और कहा कि वैश्विक आपूर्ति चेन में अड़चनों के कारण कुछ क्षेत्रों पर ज्यादा निर्भरता की समीक्षा की जा रही है। वित्तमंत्री ने भारत में उबर की विस्तार योजना की जानकारी देते हुए कहा कि टेक्नोलॉजी कंपनियां यातायात को मजबूत बनाने और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इंदौर की आईटी कंपनी द्वारा स्वच्छ भारत कोष में बहुत बड़ा सहयोग

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

सेरोसॉफ़्ट सॉलूशन्स प्राइवेट लिमिटेड ने समाज के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए स्वच्छ भारत कोष में 23 लाख की एक बड़ी राशि का सहयोग किया। इंदौर स्थित सॉफ्टवेयर निर्माणकर्ताओं में एक बड़ा व सम्मानित नाम है सेरोसॉफ़्ट। सेरोसॉफ़्ट ने सदैव समाज के प्रति अपने कर्त्तव्य का पालन किया है। हाल ही में कंपनी को देश की एक प्रतिष्ठित मीडिया ग्रुप द्वारा लगातार तीसरे साल इंडिआस ग्रोथ चैम्पियन 2022 अवार्ड से समान्नित किया गया। इसके पूर्व में भी कंपनी ने अनेक पुरस्कार अपने नाम किये हैं जैसे की डेलॉइट टेक्नोलॉजी फ़ास्ट 50 इंडिया 2018 एवं 2019, टेक्नोलॉजी फ़ास्ट 500 APAC 2018 एवं 2019, रेड हेरिंग टॉप 100 ग्लोबल इत्यादि। सेरोसॉफ़्ट द्वारा स्वच्छता कोष में मिलने वाले दान की धनराशि का उपयोग नये स्कूलों की स्वच्छता, सरकारी प्राइमरी व माध्यमिक स्कूलों के साथ आंगनवाड़ी में भी स्वच्छता पर जोर दिया जाएगा।

सेरोसॉफ़्ट के सीईओ एवं एम.डी. श्री अर्पित बड़जात्या जी ने स्वच्छ भारत कोष को किये अपने योगदान के बारे में बताया कि- ' इंदौर शहर ने स्वच्छता के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए लगातार 5 वर्ष, भारत के स्वच्छ्तम शहर का पुरस्कार अपने नाम किया है। इस स्वच्छता अभियान में समाज के अनेक संस्थानों ने बढ़-चढ़ कर अपना योगदान दिया है जिनमें सेरोसॉफ़्ट अग्रणी है और समाज के प्रति अपने दायित्व को निभाने के लिए भविष्य में भी इस महाअभियान का एक महत्त्वपूर्ण प्रतिभागी होने के लिए प्रतिबद्ध है।

News यू केन USE

हाजिर मांग से कच्चे तेल की वायदा कीमतें चढ़ीं

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

मजबूत हाजिर मांग के बीच कारोबारियों द्वारा अपने सौदों का आकार बढ़ाने से बुधवार को कच्चे तेल का वायदा भाव छह रुपये चढ़कर 7,875 रुपये प्रति बैरल पर पहुंच गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में कच्चे तेल का मई डिलिवरी वाला अनुबंध छह रुपये या 0.08 प्रतिशत की बढ़त के साथ 7,875 रुपये प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। इसमें 5,580 लॉट के लिए कारोबार हुआ। वैश्विक स्तर पर वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट कच्चे तेल का भाव 0.88 प्रतिशत की बढ़त के साथ 102.60 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। ब्रेंट कच्चा तेल 0.95 प्रतिशत के उछाल के साथ 105.99 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।

अडाणी एंटरप्राइजेज ने मीडिया कारोबार के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी का गठन किया

नयी दिल्ली। एजेंसी

अडाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) ने बुधवार को अपनी अनुषंगी इकाई एएमजी मीडिया नेटवर्क्स के गठन की घोषणा की। पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी (डब्ल्यूओएस) निश्चित समय में अपना कारोबारी परिचालन शुरू करेगी। एईएल ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा, "कंपनी ने 26 अप्रैल, 2022 को एएमजी मीडिया नेटवर्क लिमिटेड नाम से एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी का गठन किया है। इस इकाई का गठन एक-एक लाख रुपये की शुरुआती अधिकृत और चुकता शेयर पूंजी के साथ किया गया है। यह इकाई विभिन्न प्रकार की मीडिया गतिविधियों मसलन प्रकाशन, विज्ञापन, प्रसारण, वितरण आदि का कामकाज करेगी।"

बीते वित्त वर्ष में भारत का रसायन निर्यात 29.3 अरब डॉलर पर पहुंचा

नयी दिल्ली। एजेंसी

कृषि रसायन, डाई (कपड़ों की रंगाई में इस्तेमाल होने वाला रंग) और विशेष रसायन क्षेत्रों के अच्छे प्रदर्शन के कारण बीते वित्त वर्ष 2021-22 में रसायन निर्यात 29.3 अरब डॉलर पर पहुंच गया। वाणिज्य मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी।

भारत, विश्व में रसायनों का छठा सबसे बड़ा उत्पादक है। वहीं एशिया में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। निर्यात के मामले में भारत 14 वें स्थान पर है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "वर्तमान में भारत डाई के उत्पादन में अग्रणी है। वहीं दुनिया के डाईस्टफ निर्यात में 16-18 प्रतिशत का योगदान देता है। भारतीय डाई का निर्यात 90 से अधिक देशों में किया जाता है।" भारत के प्रमुख निर्यात गंतव्य अमेरिका, चीन, तुर्की, रूस और उत्तर-पूर्व एशियाई देश मसलन चीन, हांगकांग, जापान, कोरिया, ताइवान, मकाओ, मंगोलिया हैं। पिछले कुछ वर्षों से भारत का रसायन उद्योग प्रौद्योगिकी में नवाचारों और उत्पादों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दे रहा है।

इंदौर के इतिहास में पहली बार

स्कल बेस सर्जरी सोसाइटी ऑफ इंडिया का दो दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस

■ भारत और विदेशों के प्रमुख न्यूरोसर्जन्स शामिल होंगे ■ जटिल मस्तिष्क सर्जरी करने की तकनीकों पर खास बातचीत ■ इंडस्ट्री में अग्रणी कंपनियों द्वारा विकसित की गई, नई डिवाइसेस और टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन

इंदौर। स्कल बेस सर्जरी सोसाइटी ऑफ इंडिया 'स्कल बेस इंदौर 2022' की कॉन्फ्रेंस का आयोजन, लेज़र ऑडिटोरियम, एसएआईएमएस मेडिकल कॉलेज और पीजी इंस्टिट्यूट, इंदौर में 29 और 30 अप्रैल, 2022 को किया जाएगा। दो दिन चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस में भारत और विदेशों के प्रमुख न्यूरोसर्जन्स शामिल होंगे, जो मस्तिष्क की सर्जरी के विशेषज्ञ हैं। मेदांता सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल, इंदौर के न्यूरोसाइंसेस के डायरेक्टर डॉ. रजनीश कछारा उक्त कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइज़िंग चेयरमैन हैं। इसके साथ ही वे स्कल बेस सर्जरी सोसाइटी ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष भी हैं। डॉ. प्रणव घोडगांवकर, चीफ न्यूरोसर्जन, सीएचएल हॉस्पिटल, इंदौर इसके ऑर्गेनाइज़िंग सेक्रेटरी हैं। इस कॉन्फ्रेंस को इंदौर की न्यूरोलॉजिकल सोसायटी के सहयोग से किया जा रहा है।

कॉन्फ्रेंस को लेकर डॉ. रजनीश कछारा, डायरेक्टर, न्यूरोसाइंसेस, मेदांता सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल, इंदौर कहते हैं, 'यह कॉन्फ्रेंस अपने में अनूठी विशेषता रखती है, क्योंकि इस तरह की नेशनल कॉन्फ्रेंस इंदौर के इतिहास में पहली बार होने जा रही है। जैसा कि इस कॉन्फ्रेंस में देश-विदेश के जाने-माने न्यूरोसर्जन्स शिरकत कर रहे हैं, यह इसमें शामिल होने वाले लोगों को सर्जरी से संबंधित हर छोटी-बड़ी बात सीखने के साथ ही बेहतर लर्निंग एक्सपीरियंस प्रदान करेगी। इसके साथ ही सीनियर्स और जूनियर्स के बीच विचारों का बखूबी आदान-प्रदान इन दो दिनों में देखा जाएगा।'

उक्त कॉन्फ्रेंस में फैकल्टी और प्रतिनिधियों सहित लगभग 200 न्यूरोसर्जन्स अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। एंडोस्कोप और माइक्रोस्कोप के उपयोग द्वारा जटिल मस्तिष्क सर्जरी करने की तकनीकों का विवरण देते हुए कैडवेरिक वर्कशॉप्स पर भी बात की जाएगी। साथ ही प्रतिनिधियों को एक्सपर्ट्स द्वारा निर्देशित भी किया जाएगा। स्पेशलिटी के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए 50 से अधिक लेक्चर्स को शामिल किया गया है। फैकल्टी में यूएसए, जापान, यूके और ऑस्ट्रेलिया के स्पीकर्स शामिल हैं। आर्गनाइजर सेक्रेटरी डॉक्टर प्रणव ने बताया कि इंडस्ट्री में अग्रणी कंपनियों द्वारा विकसित की गई, नई डिवाइसेस और टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन भी किया जाएगा। प्रतिनिधियों के लिए इन डिवाइसेस का उपयोग करने और नई टेक्नोलॉजीस से अवगत होने का यह अद्भुत मौका है। फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री के विभिन्न सदस्य भी इस कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे हैं, जो कि अपनी टेक्नोलॉजीस और प्रोडक्ट्स का प्रदर्शन करेंगे। कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉ. बी के मिश्रा, अध्यक्ष, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ स्कल बेस सोसाइटीज़ की गरिमामयी उपस्थिति में 29 अप्रैल को किया जाएगा। इंदौर में भारत की स्कल बेस सर्जरी सोसायटी का यह पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस है। निश्चित तौर पर यह कॉन्फ्रेंस देश भर के युवा न्यूरोसर्जन्स को सीखने का एक उत्कृष्ट अनुभव प्रदान करेगी।

रूस से कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए जहाज खोजने के लिए संघर्ष कर रहा है

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत का तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) रूस के सुदूर पूर्व से 700,000 बैरल कच्चे तेल को शिप करने के लिए एक जहाज खोजने के लिए संघर्ष कर रहा है, एक बढ़ते संकेत में कि मास्को के सबसे बड़े भागीदारों में से एक जटिल व्यापार पश्चिमी प्रतिबंधों से बाधित हो गया है, रॉयटर्स ने बताया। सूत्रों का हवाला देते हुए।

ओएनजीसी सहित कई भारतीय कंपनियां, रूसी तेल और गैस परिसंपत्तियों में अपनी हिस्सेदारी रखती हैं, और जब से मास्को ने यूक्रेन पर आक्रमण किया है, भारत अधिक रूसी क्रूड खरीद रहा है, प्रसिद्ध यूराल ग्रेड छीन रहा है, जबकि अन्य खरीदारों ने रूसी निर्यात को छोड़ दिया है। ओएनजीसी की सखालिन 1 परियोजना में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी है जो एक रूसी किस्म का उत्पादन करती है जिसे सोकोल कहा जाता है, जिस पर तेल और प्राकृतिक गैस कंपनी बोली लगा रही है। सोकोल को ज्यादातर उत्तर एशिया के खरीदारों द्वारा खरीदा जाता है और दक्षिण कोरिया से लोड किया जाता है। हालांकि, मॉस्को की उस वर्ग को जहाज करने की क्षमता, जिसके लिए जहाजों की आवश्यकता होती है जो बर्फ से टूट सकते हैं, प्रतिष्ठा जोखिम के बारे में शिपर्स की चिंताओं और बीमा कवरेज खोजने में रूसी संपत्तियों के लिए बढ़ती कठिनाई से अधिक कठिन बना दिया गया है। आमतौर पर, सोकोल तेल के शिपमेंट को सबसे पहले रूस के सुदूर पूर्व में डी कैस्ट्री टर्मिनल से दक्षिण कोरिया में बर्फ-श्रेणी के जहाजों का उपयोग करके भेज दिया जाता है, जहां उन्हें एक पारंपरिक टैंकर पर लोड किया जाता है। भारतीय रिफाइनर शायद ही कभी सोकोल ग्रेड खरीदते हैं, क्योंकि मुश्किल रसद कच्चे तेल को महंगा बनाती है। दुनिया के व्यापारी बेड़े में सीमित संख्या में बर्फ वर्ग के जहाज हैं जिन्हें किसी भी समय तैनात किया जा सकता है।

ओएनजीसी दक्षिण कोरिया में येओसु के बंदरगाह तक कच्चे तेल के परिवहन के लिए रूस के सरकारी स्वामित्व वाले सोवकॉमफ्लोट द्वारा आपूर्ति किए गए बर्फ-श्रेणी के जहाजों पर निर्भर करता है, और वहां से भारतीय कंपनी खरीदारों को निर्यात करती है, ज्यादातर उत्तरी एशिया में प्रतिबंध बाधाओं को बढ़ाते हैं

हालांकि, यूक्रेन पर मास्को के आक्रमण के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और कनाडा द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंध, साथ ही एससीएफ पर विशिष्ट प्रतिबंध, एससीएफ बेड़े सहित रूसी जहाजों के लिए बीमा बनाए रखना मुश्किल बनाते हैं और पुनर्बीमा कवर। शिपिंग सूत्रों ने कहा।

शिपिंग सूत्रों ने कहा कि शिपिंग कंपनियां भी पट्टों में शामिल संभावित प्रतिष्ठा जोखिमों के डर से एशिया में रूसी तेल परिवहन के लिए कम इच्छुक हैं।

पिछले महीने, ओमानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी को सोकोल को निर्यात करने के लिए अपने टेंडर में कोई बोली नहीं मिली क्योंकि खरीदार पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण पीछे हट गए। इसके कारण ओएनजीसी ने भारत के राज्य रिफाइनर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (बीपीसीएल) को एक-एक शिपमेंट बेच दिया।

शिपिंग सूत्रों के अनुसार, बीपीसीएल कार्गो को अगले महीने दक्षिण कोरियाई बंदरगाह येओसु से उठाया जाना था, जबकि एचपीसीएल को मई के अंत में कार्गो उठाने के लिए दिया गया था। शिपिंग रिपोर्टों से पता चला है कि बीपीसीएल ने दक्षिण कोरियाई बंदरगाह से एक पोत चार्टर जांच शुरू की और मई की शुरुआत में अटलांटिस को शिपमेंट के लिए आरक्षित करने की मांग की। लेकिन सूत्रों ने कहा कि आपूर्ति विफल रही क्योंकि तेल और प्राकृतिक गैस कंपनी यात्रा को सुरक्षित करने के मुद्दों के कारण येओसु बंदरगाह के लिए एक जहाज की व्यवस्था नहीं कर सकी।

ओएनजीसी, एचपीसीएल और बीपीसीएल ने रायटर से टिप्पणी मांगने वाले ईमेल का जवाब नहीं दिया।

इस साल, भारत ने यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद से दो महीनों में रूस से दोगुना से अधिक कच्चा तेल खरीदा है, जैसा कि उसने पूरे 2021 में किया था। रूसी समुद्री क्षेत्र को ब्रिटिश एलआर और नॉर्वे के डीएनवी जैसे प्रमुख विदेशी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा जहाजों की मंजूरी सहित सेवाओं को समाप्त करने में कठिनाई हो रही है। जानकार सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया कि मॉस्को के निर्यात को एक और झटका देते हुए समुद्री ईंधन के विक्रेताओं ने स्पेन और माल्टा सहित प्रमुख यूरोपीय केंद्रों में रूसी ध्वज वाले जहाजों की सेवा बंद कर दी है। यूरोपीय संघ ने मार्च में रूसी राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों में एससीएफ को शामिल किया, जिसके साथ 15 मई को परिसमापन अवधि समाप्त होने के बाद 'किसी भी लेनदेन में प्रवेश करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निषिद्ध है'।

करोड़ों किसानों के लिए अच्छी खबर

केंद्रीय कैबिनेट ने खाद सब्सिडी बढ़ाने को दी मंजूरी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कैबिनेट ने कई बड़े निर्णय लिये हैं। इनमें से अधिकतर निर्णय किसानों के हित में लिये गए हैं। कैबिनेट ने खाद सब्सिडी बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। सरकार ने फॉस्फेटिक और पोटासिक उर्वरकों के लिए सब्सिडी को 21,000 करोड़ से बढ़ाकर 61,000 करोड़ रुपये करने का फैसला लिया है। इससे देश के 14 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचेगा। साथ ही कैबिनेट ने पीएम स्वनिधि स्कीम को दिसंबर 2024 तक बढ़ाने का फैसला लिया है। इस योजना में किसानों को कोलैटरल फ्री लोन मिलता है। पीएम स्वनिधि योजना का लाखों वेंडर्स ने फायदा उठाया है। वहीं, कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर में 540 मेगावॉट हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाने का भी फैसला लिया है। इसके अलावा सरकार इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को 820 करोड़ रुपये का फाइनेंशियल सपोर्ट देगी।

पीएम स्वनिधि योजना का भी किया विस्तार

फॉस्फेटिक और पोटासिक उर्वरकों के लिए सब्सिडी दरों को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक अप्रैल से 30 सितंबर तक चलने वाले खरीफ सीजन के लिए फॉस्फेटिक और पोटासिक उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने 60,939.23 करोड़ रुपये की सब्सिडी मंजूर की है। मौजूदा वित्त वर्ष में केंद्र का खाद सब्सिडी पर व्यय 2.10 से 2.30 लाख करोड़ रुपये के बीच उच्च रहने का अनुमान है। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह एक साल में खाद सब्सिडी पर होने वाला अब तक का सबसे अधिक खर्च होगा। वित्त वर्ष 2023 के लिए बजट में खाद सब्सिडी के लिए केवल 1.05 लाख करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया था।

रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद से काफी बढ़ गई खाद की कीमतें

रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद से गैस की कीमतों में वृद्धि देखने को मिली है। इसके चलते यूरिया उत्पादन में लगने वाली लागत भी बढ़ रही है। मुख्य कच्चे माल की कमी के चलते गैर-यूरिया खाद की कीमतें भी बुरी तरह प्रभावित हुई हैं।

अब दिसंबर 2024 तक उठा सकेंगे पीएम स्वनिधि योजना का लाभ

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को पीएम स्विनिधि योजना को दिसंबर 2024 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। इस योजना के तहत सरकार स्ट्रीट वेंडर्स को कोलैटरल फ्री लोने देती है। अर्थात इस लोन के लिए कोई गारंटी नहीं देनी होती है। योजना में सात फीसद सब्सिडी पर लोन मिलता है। सरकार का लक्ष्य साल 2024 तक इस योजना से 40 लाख वेंडर्स को फायदा पहुंचाना है। बता दें कि इस योजना में वेंडर्स को पहली किस्त के रूप में 12 महीने के लिए 10,000 रुपये के लिए लोन मिलता है। अगर समय पर पैसा चुकाया जाता है, तो दूसरी किस्त में 20,000 रुपये का लोन मिलता है। इसके बाद तीसरी किस्त में वेंडर्स को 50,000 रुपये का लोन 36 महीने के लिए मिलता है।

किसानों की आय में 10 गुना तक हुआ इजाफा

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दावा किया है कि किसानों की आय दोगुनी ही नहीं बल्कि 10 गुना हुई है। तोमर ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 'किसान भागीदारी, प्राथमिक हमारी' अभियान की शुरुआत करते हुए देश भर के किसानों के साथ बातचीत में यह कहा। तोमर ने कहा कि ऐसे प्रगतिशील किसानों को गांव-गांव जाकर खेती कर रहे लोगों को जागरुक करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नवीनतम तकनीक और सरकार की कृषि संबंधी योजनाओं से जुड़े किसान समृद्ध हुए हैं। साथ ही कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को उनके उत्पादों पर बाजार में एमएसपी से अच्छी कीमत मिल रही है। गेहूं और सरसों का किसानों को बेहतर मल्य मिला है।

रिलायंस ने रचा इतिहास

मार्केट कैप 19 लाख करोड़ रुपये के पार, ये उपलब्धि पाने वाली पहली भारतीय कंपनी

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

मुकेश अंबानी भले ही शीर्ष अरबपतियों की सूची में आठवें स्थान से फिसलकर नौवें पायदान पर पहुंच गए हों, लेकिन दूसरी ओर बुधवार को उन्होंने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के शेयरों में बुधवार को आई जोरदार तेजी के चलते कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 19 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। इसके साथ ही कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से इस स्तर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है।

सर्वकालिक उच्च स्तर पर शेयर

बुधवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर आरआईएल के शेयर 1.85 प्रतिशत बढ़कर 2,827.10 रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गए। शेयर की कीमत में तेजी आने के बाद बीएसई पर सुबह के कारोबार में कंपनी का बाजार मूल्यांकन भी बढ़कर 19,12,814 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। गौरतलब है कि बीते महीने मार्च में आरआईएल का बाजार मूल्यांकन 18 लाख करोड़ रुपये के पार चला गया था।

अंबानी की नेटवर्थ 102 अरब डॉलर

आंकड़ों पर नजर डालें तो कमाई के मामले में जहां गौतम अडानी अव्वल रहे हैं, तो वहीं मुकेश अंबानी ने भी जबरदस्त कमाई की है। इस साल अब तक आरआईएल के शेयर 19 फीसदी से ज्यादा चढ़े हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, रिलायंस इंडस्ट्रीज सभी खंडों में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। आपको बता दें कि बुधवार को मुकेश अंबानी की नेटवर्थ भी 2.75 अरब डॉलर के इजाफे के साथ 102 अरब डॉलर पर पहुंच गई है।

अबु धाबी की कंपनी से की बड़ी डील

मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज और अबु धाबी की केमिकल कंपनी ताजीज के बीच बड़ा समझौता हुआ है। अबू धाबी केमिकल्स डेरिवेटिव्स कंपनी आरएससी लिमिटेड और आरआईएल ने एथिलीन डाइक्लोराइड (ईडीसी) और पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) के परियोजना के लिए औपचारिक शेयरधारक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह शेयरधारक समझौता दो अरब डॉलर का है।

हफ्ते में 3 दिन छुट्टी और बढ़ा हुआ PF 1 जुलाई से लागू हो सकते हैं नए लेबर कोड

नई दिल्ली। एजेंसी

देश में लंबे वक्त से 4 श्रम संहिताओं के लागू होने का इंतजार किया जा रहा है। केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार कल्याण मंत्रालय ने पिछले साल ही इन श्रम संहिताओं के तहत नियमों को अंतिम रूप दे दिया था। पहले कहा जा रहा था कि 4 नए लेबर कोड अप्रैल 2022 से लागू हो सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब ऐसी खबरें हैं कि 1 जुलाई से नए लेबर कोड्स के नियम अमल में आ जाएं।हालांकि अभी तक इस बारे में आधिकारिक तौर पर कोई बयान जारी नहीं हुआ है। लेकिन कहा जा रहा है कि नई श्रम संहिताओं के लागू होने में अभी और वक्त लगेगा क्योंकि सभी राज्य नियम फाइनल नहीं कर पाए हैं।

4 लेबर कोड्स में वेतन/मजदूरी संहिता, औद्योगिक संबंधों पर संहिता, काम विशेष से जुड़ी सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यस्थल की दशाओं पर संहिता और सामाजिक व व्यावसायिक सुरक्षा संहिता शामिल हैं। मंत्रालय ने श्रम कानूनों में सुधार के लिए 44 तरह के पुराने श्रम कानूनों को चार वृहद संहिताओं में समाहित किया है। कहा जा रहा है कि इन संहिताओं को लागू करने से देश के श्रम बाजार में सुधरे नियमों-अधिनियमों का नया दौर शुरू होगा।

किन अहम सुधारों की चल रही बात

सरकार का कहना है कि नए कानून अंतरराष्ट्रीय स्तर के हैं।

इनके लागू होने पर कर्मचारियों को सप्ताह में चार दिन काम करना होगा यानी उन्हें हफ्ते में तीन दिन की छुट्टी मिलेगी। लेकिन इसके लिए हर हफ्ते 48 घंटे काम करना होगा, यानी एक दिन में 12 घंटे तक काम। अगर किसी से एक हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम कराया जाता है तो उसे ज्यादा काम करने पर ओवर टाइम दिया जाए। हालांकि 3 महीने में 125 घंटे से ज्यादा ओवरटाइम पर भी काम नहीं कर सकते। नए लेबर कोड के नियमों के मुताबिक किसी भी कर्मचारी से 5 घंटे से अधिक लगातार काम कराने की इजाजत नहीं है। 5 घंटे के बाद कर्मचारी को आधे घंटे का ब्रेक दिया जाएगा। नए लेबर कोड्स के तहत लेबर और नियोक्ता की सुविधाओं का ख्याल रखा गया है। लेबर को स्किल्स बढ़ाने का इंसेंटिव मिलेगा, रोजगार बढ़ने की भी उम्मीद है।

बढ़ेगी बेसिक सैलरी

नए वेज रूल के तहत तमाम भत्ते कुल सैलरी के 50 फीसदी से अधिक नहीं हो सकते हैं। इसकी वजह से इंप्लॉइज की बेसिक सैलरी में इजाफा होगा। मौजूदा समय में कंपनियां 25-30 फीसदी ही बेसिक सैलरी का हिस्सा रखती हैं। ऐसे में तमाम तरह के अलाउंस 70-75 फीसदी तक होते हैं। इन अलाउंस की वजह से कर्मचारियों के खाते में अधिक सैलरी आती है क्योंकि तमाम तरह के डिडक्शन बेसिक सैलरी पर होते हैं। बेसिक सैलरी बढ़ने से कर्मचारी की इन हैंड सैलरी या टेक होम सैलरी कम हो जाएगी। लेकिन ग्रेच्युटी, पेंशन और कर्मचारी व कंपनी दोनों का ही पीएफ में योगदान बढ़ जाएगा। यानी भविष्य के लिए सेविंग्स बढ़ जाएगी।

इंडस्ट्री-इंस्टीट्यूट-इंटरफ़ेस से प्रासंगिक होती शैक्षणिक योग्यता -डॉ. पुनीत कुमार द्विवेदी

वर्तमान समय त्वरित गति से परिवर्तित हो रहा है। कब कौन सा व्यापार-व्यवसाय प्रासंगिक रहेगा और कौनसे का अस्तित्व समापन की ओर बढ़ेगा, कह पाना संभव नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नवाचारों के साथ कई नये प्रयोग एवं अनुप्रयोग किये हैं और उनके क्रियान्वयन हेतु रणनीतिकार लगे हुये हैं। गुणवत्ता परक उत्कृष्ट प्रयोगमूलक शिक्षा जिसका व्यापार व्यावसाय में सर्वकार है, वही उपयोगी सिद्ध होगी। हम भारत में इंडस्ट्री 4.0 की बात कर रहे हैं जिसमें इंडस्ट्रीज़ के पूर्ण ऑटोमेशन की बात पर बल दिया जा रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग गति को तेज करने में सहायक सिद्ध हो रहा है। यह विडंबना है कि शिक्षण संस्थानों में जो पाठ्यक्रम है उसका उद्योग अथवा व्यापार में उतनी प्रासंगिकता नहीं है।समय-समय पर पाठ्यक्रमों में परिवर्तन, इंडस्ट्री ओरियेंटेड पाठ्यक्रम का निर्माण एवं क्रियान्वयन एक प्रमुख चुनौती बनी हुयी है। कारण है कि इंडस्ट्री और शिक्षण संस्थानों में आपसी तालमेल की कमी, एक साथ शोध एवं विकास की चर्चा ना करना, बदलते परिवेश के अनुसार एक साथ नहीं बदल पाना, जो चल रहा है वही चलता रहे का भाव इत्यादि। बदलते परिवेश में अब यह संभव नहीं। समय-समय पर अप-टू-डेट होना समय की माँग है अन्यथा फेल्योर संभव है। कोरोना काल में शिक्षा के गुणवत्ता के स्तर में कमी आयी है। सभी को पास कर देना, ओपन

डॉ. पुनीत कुमार द्विवेदी

मॉडर्न ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स, इंदौर में प्रोफ़ेसर एवं समूह निदेशक की भूमिका में कार्यरत हैं।

बुक, ऑनलाईन परीक्षा, ऑनलाईन लेक्चर्स, ऑन लाईन प्रैक्टिकल परीक्षा तात्कालिक समस्या थी परंतु इसके परिणाम भयावह एवं दूरगामी प्रभाव वाले होंगे, यह चिंता का विषय भी है। प्रश्न यह भी उठता है है कि क्या उच्च शिक्षा सबके लिये आवश्यक है ? आज जब हम उद्यमिता एवं कौशल विकास की बात करते हैं तो कई बार संदेह की भी स्थिति आती है और मंशा पर संदेह भी होता है। स्टार्टअप्स के क्षेत्र में सरकार का फ़ोकस प्रशंसनीय है और विगत कुछ वर्षों में नवाचार और स्टार्टअप्स के क्षेत्र में भारत की अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति उल्लेखनीय भी है। यह गर्व का विषय है। स्टार्टअप्स के क्षेत्र में अपार संभावनायें भी हैं और बहुत कुछ संस्थागत विकास करने की आवश्यकता भी। ए.आई.सी.टी.ई, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई पहल- इंस्टीट्यूट इनोवेशन काऊंसिल के द्वारा देश के प्रत्येक उच्च शिक्षा एवं तकनीकि शिक्षा के शैक्षणिक संस्थानों में नवाचार और स्टार्टअप्स की नर्सरी तैयार हो रही है। वहीं दूसरी तरफ़ स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स के द्वारा रोबोटिक्स की शिक्षा प्रदान कर नवाचार का ओरिएंटेशन उस दिशा में सोचने के लिये प्रेरित कर रहा है। परंतु, ये सब तभी सफल हैं जब शैक्षणिक संस्थानों का शोध संस्थानों एवं उद्योगों के साथ सामंजस्यपूर्ण समन्वयन नियमित रूप से होता रहे। इंडस्ट्री-इंस्टीट्यूट-इंटरफ़ेस के माध्यम से थियरी और प्रैक्टिकल के बीच सामंजस्य स्थापित हो सक पायेगा। विद्यार्थियों में अच्छी समझ डेवेलप होगी जो उन्हें एक अच्छा, प्रभावशाली, कुशल पेशेवर बना सक पायेगी। ज़िम्मेदारी शिक्षक समाज एवं उद्योग नेतृत्वकर्ताओं की होगी।

कब है शनि अमावस्या? जानें तिथि, महत्व और 8 शुभ उपाय

धार्मिक शास्त्रों में वर्षभर में आने वाली सभी अमावस्या तिथियों का विशेष महत्व माना गया है। इस वर्ष वैशाख मास में पड़ने वाली शनि अमावस्या 30 अप्रैल 2022 को मनाई जा रही है...

महत्व : ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि अमावस्या के दिन भगवान शनि देव का दिन पड़ने के कारण ही इसे शनिचरी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन पितृ तर्पण, पितृ कर्मकांड, नदी-सरोवर स्नान तथा अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना बेहद शुभ एवं पुण्य फलदायी माना जाता है। इस दिन शनि देव का पूजन करके शनि पीड़ा से मुक्ति की कामना भी की जाती है। शनि की अनुकूलता से व्यक्ति को चल रही शनि की साढ़ेसाती, शनि ढैय्या और कुंडली में मौजूद शनि दोष का प्रभाव समाप्त होकर सभी कार्यों में आने वाली समस्त बाधाएं समाप्त होती हैं। इतना ही नहीं जहां व्यापारी वर्ग को तरक्की मिलती है, वहीं नौकरीपेशा जातकों को पदोन्नति भी मिलती है।

ज्योतिष की मानें तो अमावस्या के दिन अगर शनिवार आ जाए तो इसका काफी महत्व बढ़ जाता है। इस बार 30 अप्रैल को सूर्य ग्रहण तथा स्नान दान श्राद्ध अमावस्या होने से भी इस दिन बेहद विशेष संयोग है। मान्यता के अनुसार ग्रहण के दिन गंगा, यमुना आदि नदियों पर स्नान एवं दान करने से ईश कृपा की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही शनि अमावस्या के दिन कुछ खास उपाय करने से जीवन के समस्त कष्ट दूर होकर

शनि की अनुकूलता तथा प्रबल धन प्राप्ति के योग भी बनते हैं।

8 खास उपाय

1. शनिचरी अमावस्या के शनि और हनुमान जी का पूजन करने का विशेष महत्व है। शनि पूजा के लिए सबसे विशेष समय रात्रि या गोधूलि अर्थात शाम का समय होता है। अतः इस दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप यह कार्य कर सकते सकते हैं।

2. जो व्यक्ति बीमारी से ग्रसित हैं या जिन्हें बार-बार वाहन दुर्घटना का सामना करना पड़ रहा हैं, तो उन्हें शनि शांति की पूजा करनी चाहिए, इससे रोग और दुर्घटना से निजात मिलेगी।

3. शनि अमावस्या के दिन भगवान शनि देव का पूजन-अर्चन करने से वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियां समाप्त होती हैं।

4. जिन जातकों पर शनि की साढ़ेसाती अथवा शनि का ढैय्या चल रहा है, उन्हें शनि अमावस्या के दिन शनि की विशेष आराधना करनी चाहिए।

5. इस दिन शनि के बीज मंत्रों तथा शनि की वस्तुओं का दान करना चाहिए। लोहा, उड़द दाल, तेल, पुराने वस्त्र, जूते-चप्पल आदि का दान तथा तली हुई खाने-पीने की चीजों का दान- जैसे समोसा, कचोरी, भजिए आदि का दान निर्धनों को करना उचित रहेगा।

6. जिन जातकों को कड़ी मेहनत के बाद भी मनोवांछित फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं, उन्हें हर शनिवार अपने शरीर तेल की मालिश करनी चाहिए। इससे स्वास्थ्य लाभ के साथ-साथ रुके हुए काम भी बनने लगते हैं।

7. शनि की शांति एवं शुभता पाने के लिए शनि अष्टक, शनि चालीसा, शनि स्तवराज और शनि स्तोत्र का पाठ करें।

8. इस दिन शिव जी तथा हनुमान जी के पूजन के साथ-साथ बजरंग बाण, हनुमान चालीसा और संकटमोचन हनुमानाष्टक का पाठ करने से भी शनि देव प्रसन्न होका वरदान देते हैं।

रोग, दोष, भय दूर करते हैं भगवान काल भैरव

प्रत्येक माह आने वाले कालाष्टमी व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। इस व्रत में भगवान शिव के कालभैरव रूप की पूजा का विधान है। प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह व्रत रखा जाता है। कालाष्टमी व्रत करने से शत्रुओं का भय और दुर्भाग्य दूर होता है तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान काल भैरव की उपासना से अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। परिवार में सुख-शांति व आरोग्य की प्राप्ति होती है। भगवान काल भैरव की पूजा से रोग, दोष, भय से मुक्ति मिलती है। भगवान कालभैरव के पूजन और व्रत से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हाथ में त्रिशूल, तलवार और डंडा होने के कारण भगवान काल भैरव को दंडपाणि भी कहा जाता है। इस व्रत में श्री भैरव चालीसा का पाठ करें। भगवान भैरव के मंदिर में जाकर सिंदूर, सरसों का तेल, नारियल, चना, पुए और जलेबी चढ़ाकर भक्ति भाव से पूजन करें। भगवान भैरव के समक्ष सरसो के तेल का दीपक जलाएं और श्रीकालभैरवाष्टकम् का पाठ करें। कालाष्टमी के दिन से लेकर 40 दिनों तक लगातार काल भैरव का दर्शन करने से भगवान भैरव प्रसन्न होते हैं। इस व्रत में काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं। शाम को आरती के बाद फलाहार करें। अगले दिन सुबह स्नान-पूजा पाठ के बाद ही व्रत खोलें। रात में चंद्रमा को जल अर्पित अवश्य करें।

अक्षय तृतीया के 10 सरल उपाय

मनचाही खुशी के लिए जरूर आजमाएं

3 मई 2022 मंगलवार को अक्षय तृतीया पर 50 वर्षों के बाद ग्रहों का दुर्लभ संयोग और शुभ योग बन रहा है। साथ ही इस दिन अबूझ मुहूर्त रहता है। यानी की इस पूरे दिन ही शुभ मुहूर्त रहेगा। आओ जानते हैं इस दिन कौनसे 10 सरल उपाय करें।

1.रामरक्षा स्तोत्र का पाठ : जो लोग बीमारियों से ग्रस्त हैं उनको आज के दिन रामरक्षा स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए

2. तीर्थ स्नान और तर्पण : अक्षय तृतीया के दिन तीर्थ स्नान तथा पितृ तर्पण का विशेष महत्व है। अतः इस दिन यह कार्य अवश्य करें। इससे पितृदोष से मुक्ति मिलेगी।

3. रामचरित मानस : इस दिन श्री रामचरितमानस के अरण्य काण्ड का पाठ करना चाहिए। इस काण्ड में भगवान राम ऋषियों और महान संतों को दर्शन देते हैं और उनके जन्म जन्मान्तर के पुण्य का फल प्रदान करते हैं। इस काण्ड का पाठ करने से भगवान श्री राम की भक्ति प्राप्त होती है।

4. तिजोरी में रखें ये : अक्षय तृतीया के दिन अपने पूजा स्थान में एकाक्षी नारियल को लाल वस्त्र में बांधकर स्थापित करें। व्यापारीगण एकाक्षी नारियल को लाल वस्त्र में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। इस दिन चांदी की डिब्बी में शहद और नागकेसर भरकर अपनी तिजोरी में रखें। इससे धन धान्य में वृद्धि होगी।

5. कुंभ दान : इस दिन जल से भरा मिट्टी का घड़ा मंदिर में दान करें। साथ ही कुल्हड़, सकोरे भी दान करें। इससे जीवन में सुख और शांति में वृद्धि होगी।

6. अन्न दान : इस दिन सत्तू, ककड़ी, खरबूजा, चावल, दूध, दही, घी, फल, इमली, सब्जी, शहद, पंचमेवा, पंचधान, सीधा दान आवश्य करें।

7. भाग्योदय : अगर आपका भाग्योदय नहीं हो रहा है, तो अक्षय-तृतीया के दिन प्रातः उठते ही सर्वप्रथम 11 गोमती चक्रों को पीसकर उनका चूर्ण बनाकर अपने घर के मुख्य द्वार के सामने अपने ईष्ट देव का स्मरण करते हुए बिखेर दें। इस प्रयोग से कुछ ही दिनों में भाग्योदय होना शुरू होगा तथा दुर्भाग्य समाप्त होकर जीवन में खुशहाली आएगी।

8. व्यापार : अगर आप व्यापार अधिक लाभ पाना चाहते हैं तो 27 गोमती चक्र लेकर पीले या लाल रेशमी कपड़े में बांधकर अपने व्यापारिक स्थान अथवा प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार पर बांध दें, यह कार्य करने भर से आपको व्यापार में आशानुरूप लाभ मिलने लगेगा।

9. सुख-शांति : अक्षय तृतीया के दिन घर में सुख-शांति बनाए रखने के लिए ग्यारह गोमती चक्रों को एक लाल रेशमी कपड़े में बांधकर चांदी की डिब्बी में रखकर पूजा स्थान में रख दें, इससे घर में हमेशा सुख-शांति का वास बना रहता है।

10. माता पूजा : अक्षय तृतीया ललिता सहस्त्रनाम व श्रीसूक्त का पाठ कर मां त्रिपुरसुन्दरी एवं माता लक्ष्मी का अर्चन करें। इससे धनलाभ होगा।

इन उपायों से प्रसन्न होते हैं वास्तु देवता, घर में आती है सकारात्मकता

संतोष वाधवानी
रत्न एवं वास्तु विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु एसोसिएशन प्रदेश प्रवक्ता

जीवन में सकारात्मकता बनाए रखने के लिए घर की साज-सज्जा बहुत जरूरी है। घर अगर स्वच्छ है तो वास्तु देवता की कृपा बनी रहती है। वास्तु शास्त्र में सकारात्मकता बढ़ाने के लिए कुछ आसान से उपाय बताए गए हैं, आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। अपने घर की दीवारों पर स्वास्तिक का चिह्न बनाएं, ऐसा करने से माना जाता है कि घर में देवताओं का वास होता है। हल्दी-चंदन से बना स्वास्तिक सुंदरता बढ़ाने के साथ नकारात्मक ऊर्जा को घर से दूर रखता है। घर में आक्रामक पशु-पक्षियों के चित्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे घर के सदस्यों में वैमनस्य की भावना बढ़ती है। घर की पूर्व दिशा में सूर्योदय की तस्वीर लगाएं। इससे बच्चों में ऊर्जा, उत्साह और उमंग बनी रहती है। मन एकाग्र होता है। घर के हर कोने को सुगंध से महकाएं। घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। अमावस्या के दिन घर की सफ़ाई का नियम बनाएं। जब भी घर में पोंछा लगाएं तो पानी में थोड़ी-सी हल्दी ज़रूर मिलाएं। घर के अंदर प्लास्टिक के फूल व पेड़-पौधे ना रखें। रसोईघर में रात के जूठे बर्तन रखने से व्यापार में हानि हो सकती है। रात में ही रसोईघर को साफ़ करें। शयनकक्ष में पानी न रखें। ऐसा करने से कर्ज़ व उधार की स्थिति बन सकती है। रोज़ाना शाम को घर में कर्पूर जलाने से धन में वृद्धि होती है। कभी भी घर की तिजोरी में परफ्यूम या इत्र न रखें। अपने घर में वर्ष में दो बार हवन कराएं। इससे वास्तु देवता प्रसन्न होते हैं। घर के मध्य स्थान पर कभी भी भारी समान नहीं रखें। घर के मुख्य द्वार पर गाय और बछड़े को रोटी और गुड़ खिलाएं। बुधवार के हरा चारा खिलाएं। रोजाना पक्षियों को दाने डालें। घर या बालकनी में सूखे पेड़ या पौधे नहीं रखें। हरे भरे पेड़ पौधे से घर को सज़ाएं।

प्लेटिनम लव बैंड्स के बेहतरीन और दिलकश डिजाइन

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

अंगूठियों के आदान-प्रदान की एक प्रथा, जिसे हम सगाई के नाम से जानते हैं, यह वह क्षण है जो एक युगल के लिए जीवन भर साथ निभाने की दिशा में पहला कदम होता है। यह वह पल होता है जब प्रेमी युगल साथ मिलकर यह महसूस करते हैं कि आज उनकी जिंदगी के सबसे सुंदर दिन है, और अब उनका आने वाला भविष्य उन्हें साथ मिलकर ही बनाना है। इस दिन से यह युगल साथ मिलकर एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दोस्त के रूप में एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे का समर्थन करते हैं, कभी-कभी आलोचना भी करते हैं, जीवन में ऊंचाई हासिल करने के लिए अपना पूरा प्रयास करते हैं तथा जीवन में एक दूसरे का साझेदार बनकर प्रतिबद्धता के साथ अपने एक विशेष जीवन की शुरुआत करते हैं। चाहे सगाई जैसा भव्य समारोह हो या बेहद निजी और अंतरंग पल हों, यह क्षण आपकी जिंदगी के सबसे अद्वितीय एवं असाधारण पल हैं जिन्हे प्लेटिनम से सजाया जाना चाहिए।

सितारों में जन्मा और सोने से 30 गुना अनूठा है, प्लेटिनम दुनिया भर के चुनिंदा स्थानों में पाया जाता है, जिससे इसकी अत्यधिक मांग है। इस धातु का एक और अनूठा गुण है, यह समय और परिस्थितियों के साथ अपरिवर्तित रहता है। यह अपनी प्राकृतिक सफेद चमक या रूप को कभी नहीं खोता है, ठीक उसी तरह जैसे प्यार हमेशा के लिए अमर रहता है। अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में 95ङ्ग शुद्ध प्लेटिनम के साथ युगल जोड़े एक दूसरे के लिए सबसे मजबूत सहयोगी होने का वादा करते हैं। प्रत्येक पीस पर मुहर लगी पीटी 950 का निशान धातु की शुद्धता का प्रमाण है, जो कि सबसे अधिक कीमती आभूषणों में से एक है। और इन जोड़ों के प्यार की ताकत की तरह, प्लेटिनम का उच्च घनत्व यह सुनिश्चित करता है कि यह जोड़ा जीवन भर के लिए इस कीमती प्लेटिनम को मजबूती से और सुरक्षित रूप से धारण करे।

जटिल रूप से तैयार किए गए प्लेटिनम लव बैंड्स, एक ऐसे प्रेम का जश्न मनाते हैं जो वास्तव में अनूठा है, जो पारस्परिकता, सम्मान, समानता और दोस्ती के आधुनिक और प्रगतिशील मूल्यों पर आधारित है, जो आज किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होता है। अपने अलग रूप, अद्वितीय और आधुनिक डिजाइन के साथ, ये प्लेटिनम लव बैंड्स आज के युवाओं तथा जनरेशन जेड को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इस सीजन में, प्लेटिनम लव बैंड्स का 'एंगेजमेंट एडिशन' एक जोड़े की अपनी अनूठी प्रेम कहानी बताता है, जिसमें इस विशेष अवसर के लिए आदर्श युगल बैंड उपलब्ध हैं। ट्रेंड में चल रहे ज्यामितीय डिजाइन, जटिल पैटर्न, आकर्षक रेखाएं और कीमती प्लेटिनम पर विशेष डिजाइन उकेरना एक विशेष तरह के प्रेम की कहानियों से प्रेरित है। प्लेटिनम लव बैंड की प्रत्येक जोड़ी एक ऐसे पल का जश्न मनाने के लिए बिलकुल आदर्श है जो जीवन भर उनके दिलों में अंकित रहेगा।

मेटल की ओवरलैपिंग परतें एक अटूट बंधन बनाने के लिए एक साथ आती हैं, यह दिखाता है कि आप दोनों एक साथ कितने मजबूत हैं। और एक ऐसे प्यार के लिए जो आपके जितना ही अनूठा और मजबूत है, केवल प्लेटिनम मेटल ही है जो इस प्रेम के सामान है। यह कलेक्शन भारत के 1500 से अधिक प्रमुख ज्वैलरी स्टोर्स पर उपलब्ध है। प्लेटिनम डेज़ ऑफ़ लव के और अधिक डिज़ाइनों का अन्वेषण करें, जो पूरे भारत में प्रमुख ज्वैलरी रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध हैं।

पौधारोपण को समर्पित भारत के पहले एनएफटी की पेशकश

सीग्राम्स 100 पाइपर्स 'नाऊ फंडिंग टुमॉरो' लेकर आया

इंदौर। एजेंसी

100 पाइपर्स 'प्ले फॉर ए कॉज़' प्लेटफॉर्म के तहत एआरओएच फाउंडेशन के साथ साझेदारी में, 100 पाइपर्स ने एक साल में 1 मिलियन (10 लाख) पेड़ लगाने का संकल्प लिया है। सीग्राम्स 100 पाइपर्स का 'प्ले फॉर ए कॉज़' प्लेटफॉर्म बीते वर्षों में ऐसे कार्यों को सहयोग देने में सबसे आगे रहा है, जो समाज को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। इस प्रकार ब्राण्ड का मूल प्रस्ताव 'अच्छाई के लिये याद रहें' (बी रिमेम्बर फॉर गुड) अनुभव करने योग्य तरीके से साकार होता है। इस साल 100 पाइपर्स 'प्ले फॉर ए कॉज़' ने एआरओएच फाउंडेशन के साथ साझेदारी में एक वर्ष में 1 मिलियन (10 लाख) पेड़ लगाने का वादा करके भविष्य को ज्यादा हरित बनाने का संकल्प लिया है। 100 पाइपर्स ने यह महत्वपूर्ण कैम्पेन 22 अप्रैल को 'अर्थ डे' पर शुरू किया है। 100 पाइपर्स ने भविष्य की तकनीकोंको भी अपनाया है और पौधारोपण को समर्पित भारत के पहले पर्यावरण-थीम वाले एनएफटी 'नाऊ फंडिंग टुमॉरो' को लॉन्च किया। 'पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण' की थीम पर आधारित 13 प्रतिष्ठित एनएफटी को 22 अप्रैल 2022 को लॉन्च किया गया था जिन्हें प्लेः//हुंह.म्दस/100ज्जी प्लेटफॉर्म से खरीदा जा सकता था। और, लॉन्च के महज 10 मिनट के भीतर सभी 13 एनएफटी बिक गए।

एनएफटी की बिक्री से मिली रकम एआरओएच फाउंडेशन को स्थानांतरित की जाएगी और इसके अलावा, इससे व्यापक पौधारोपण पहल के एक बड़े हिस्से में योगदान देने में भी मदद मिलेगी। ब्रांड ने पौधारोपण की जरूरत को लेकर जागरुकता बढ़ाने के लिए एक अनूठा डिजिटल अभियान भी शुरू किया है। इसने दर्शकों से एनएफटी बिक्री में हिस्सा लेकर सीटीओ- चीफ ट्री ऑफीसर बनने के लिए आह्वान किया है। इससे न सिर्फ उनका कलेक्?शन बढ़ेगा बल्कि पौधे उगाने में भी मदद मिलेगी। प्रत्येक एक्सक्लूसिव एनएफटी ब्रांड के लिए 10 पौधे रोपे जाएंगे और प्रत्येक दुर्लभ एनएफटीके लिए 2 पौधे लगाए जाएंगे।

इस पहल पर अपना रोमांच व्यक्त करते हुए, पर्नोड रिकार्ड इंडिया के चीफ मार्केटिंग ऑफीसर कार्तिक मोहिन्द्रा ने कहा, 'सीग्राम्?स 100 पाइपर्स विचार और नवाचार के नेतृत्व में विश्वास करता है। 'प्ले फॉर ए कॉज़' के म्यूजिक इवेंट्स हमारे ब्राण्ड के महत्वपूर्ण अनुभव हैं, जो 'अच्छाई के लिये याद रहें' के सिद्धांत को साकार करते हैं। इस साल 'प्ले फॉर ए कॉज़ का लक्ष्य है दो अनूठे तरीकों से पौधारोपण और इको-रिजनरेशन के कार्य को सहयोग देते हुए युवाओं के साथ ज्यादा मजबूती से जुड़ना। 'अर्थ डे 2022' से 100 पाइपर्स एक साल तक पूरे भारत में 1 मिलियन पेड़ लगाने के लिये एआरओएच फाउंडेशन के साथ मिलकर काम करेगा। इस पहल पर अपने विचार साझा करते हुए, एआरओएच फाउंडेशन की फाउंडर प्रेसिडेंट एवं सीईओ डॉ. नीलम गुप्ता ने कहा, 'हमारे लिए अपनी धरती के लिये निवेश करना इतना स्पष्ट और महत्वपूर्ण पहले कभी नहीं रहा। सीग्राम्स 100 पाइपर्स 'प्ले फॉर ए कॉज़' के साथ हमारा गठबंधन पूरे भारत में 1 मिलियन पेड़ लगाने के अभियान के साथ पर्यावरण की सुरक्षा के लिये हमारे प्रयासों को बढ़ावा देने का सबसे बढिया प्लेटफॉर्म है।

भारत का खुदरा उद्योग 2032 तक 2,000 अरब डॉलर तक पहुंचेगाः रिपोर्ट

मुंबई। एजेंसी

देश का खुदरा उद्योग महामारी के प्रकोप से उबरने के बाद एक बार फिर वृद्धि के रास्ते पर चल पड़ा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, उद्योग का आकार 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ 2032 तक बढ़कर 2,000 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार खाद्य और किराना, रेस्तरां और त्वरित सेवा रेस्टोरेंट (क्यूएसआर), तथा टिकाऊ उपभोक्ता सामान जैसे कुछ खंड कोविड से पहले के स्तर से उबर गए हैं, जबकि आभूषण, परिधान और फुटवियर जैसे खंड पूरी तरह से पुनरुद्धार की राह पर हैं। बीसीजी के प्रबंध निदेशक और वरिष्ठ भागीदार अभीक सिंघी ने कहा, ''भारतीय अर्थव्यवस्था को खपत से बढ़ावा मिल रहा है और हम देख रहे हैं कि कोविड महामारी के चलते दो साल के ठहराव के बाद खपत में वृद्धि सकारात्मक हो गई है।'' उन्होंने कहा कि भारतीय खुदरा उद्योग का आकार अगले 10 वर्षों में लगभग 2,000 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। सिंघी के मुताबिक, अगले दशक में संगठित खुदरा विक्रेता ऑफलाइन और ऑनलाइन, जैसे सभी प्रारूपों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। रिपोर्ट के अनुसार, भारत की खपत महामारी से पहले लगभग 12 प्रतिशत की दर से बढ़ रही थी और महामारी के दौरान नकारात्मक क्षेत्र में चली गई थी। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि अब खपत 17 प्रतिशत की दर से बढ़ने के साथ महामारी-पूर्व के स्तर को पार कर गई है।

भारत में जल के संसाधन प्रदान करने के लिए

एडब्लूएस ने वाटर डॉट ओआरजी और वाटरएड के साथ गठबंधन किया

इंदौर। एजेंसी

एमेज़ॉन कॉम कंपनी, एमेज़ॉन वेब सर्विसेज़, इंक. (एडब्लूएस) ने घोषणा करके बताया कि इसकी सामुदायिक जल परियोजनाओं ने वैश्विक नॉनप्रॉफिट्स वाटर डॉट ओआरजी और वाटरएड के साथ गठबंधन में साल 2020 से भारत में महाराष्ट्र, तेलंगाना, और आंध्रप्रदेश में 250,000 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराया है। आगे भी, एडब्लूएस भारत एवं विश्व में अपने कार्य संचालन में पानी की बचत में सुधार लाने, सतत स्वच्छता कार्यों का विकास करने, स्वच्छ जल की उपलब्धता बढ़ाने और जल संसाधनों का संरक्षण करने पर केंद्रित अभियानों के विस्तार के लिए वाटर डॉट ओआरजी, वाटरएड, एवं अन्य ग्लोबल नॉनप्रॉफिट्स के साथ अपने कार्यों को जारी रखेगा।

माईकल मयर्निक वाटर डॉट ओआरजी हेड ऑफ कॉर्पोरेट पार्टनरशिप्स ने कहा भारत में एडब्लूएस द्वारा वाटर डॉट ओआरजी को दिए गए सहयोग ने महाराष्ट्र तेलंगाना, और आंध्रप्रदेश में 210,000 से ज्यादा लोगों के लिए दीर्घकालिक और जलवायु के प्रति दृढ़ जल व स्वच्छता समाधान संभव बनाए हैं उन्होंने आगे कह इंस्टॉलेशंस में घरेलू पाईप्ड कनेक्शन वॉटर टैप्स, रेनवाटर हार्वेस्टिंग एवं स्टोरेज, टॉयलेट्स, बोरवैल्स, सामुदायिक वाटर फिल्ट्रेशन, और इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार शामिल हैं। इन प्रोजेक्ट्स से हर साल अनुमानित 500 मिलियन लीटर रिकरिंग वाटर वॉल्यूम बेनेफिट मिलता है। भारत में वाटरएड के चीफ एग्ज़िक्यूटिव वीके माधवन ने कहा सुरक्षित एवं निश्चित पेयजल को मूर्त रूप देने के लिए हमें सुनिश्चित करना होगा कि पानी का स्रोत सतत बना रहे।'' उन्होंने कहा, ''हमें एडब्लूएस के सहयोग से भारत में इस गंभीर समस्या को संबोधित करने की खुशी है। हैदराबाद में वाटरएड ने स्कूलों एवं सामुदायिक संस्थानों में अनेक रेनवाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं का निर्माण किया है, ताकि इन समुदायों के लिए जल की उपलब्धता बढ़ाई जा सके। हमारे प्रोजेक्ट से आज तक अकेले हैदराबाद में 23,000 से ज्यादा लोगों को लाभ मिला है। एडब्लूएस द्वारा विस्तृत सहयोग द्वारा इन स्थानों के आस-पास के समुदायों को जल संसाधनों की सुरक्षित उपलब्धता प्रदान करने के प्रयासों तथा लोगों को जल संरक्षण के महत्व के बारे में शिक्षित करने के अभियानों का लाभ मिल सकेगा।''

एडब्लूएस में ग्लोबल वाटर सस्टेनेबिलिटी लीड, विल हेवेस ने कहा जल एक बहुमूल्य संसाधन है, और हम दुनिया में अपने संचालन के क्षेत्रों में समुदायों के बीच सकारात्मक मौजूदगी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं उन्होंने कहा भारत में ये सुरक्षित जल कार्यक्रम परिवारों और स्थानीय समुदायों के लिए महत्वपूर्ण हैं, और उनसे भारत में 250,000 से ज्यादा लोग लाभान्वित हो चुके हैं। वाटर डॉट ओआरजी और स्थानीय संगठनों के साथ गठबंधन में, एडब्लूएस भारत के तीन राज्यों में किफायती लोन प्रदान करता है, ताकि नज़दीकी समुदायों को अपने-अपने घरों में पाईप्ड वॉटर कनेक्शन और टॉयलेट्स स्थापित करने के लिए वित्त प्राप्त हो सके। वाटरएड के साथ एडब्लूएस तेलंगाना और आंध्रप्रदेश में रेनवाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वॉटर रिचार्ज सिस्टम, पाईप्ड वॉटर इंस्टॉलेशंस एवं सामुदायिक जागरुकता कार्यक्रमों में मदद करता है 1.38 बिलियन लोगों की आबादी वाले भारत देश में ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण हैं।

वाटर डॉट ओआरजी के मुताबिक 6 प्रतिशत से ज्यादा भारतीयों के पास सुरक्षित जल की कमी है। घरों में पानी के कनेक्शन और टॉयलेट्स की कमी के कारण पानी से होने वाली बीमारियां, विकास में रुकावट और मृत्यु तक हो सकती है। इसके अलावा, कोविड-19 महामारी के संकट के कारण भारत में परिवारों का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए सुरक्षित जल की उपलब्धता बहुत आवश्यक हो गई है। भारत में वाटर डॉट ओआरजी और वाटरएड का गठबंधन एडब्लूएस द्वारा पानी को संरक्षित किए जाने का एक तरीका है। एडब्लूएस के लिए, अपने कार्यों का संचालन सतत बनाए रखने का एक मतलब कूल डेटा सेंटर्स में इस्तेमाल होने वाले पानी की मात्रा में कमी लाना भी है। एडब्लूएस का व्यवहारिक दृष्टिकोण इसके डेटा सेंटर के ऑपरेशंस में ऊर्जा और जल की खपत में कटौती करता है।

बक्कल म्यूकोसल ग्राफ्ट यूरेथ्रोप्लास्टी द्वारा यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर डिसीज़ से मिला मरीजों को नया जीवन

यूरेथ्रोप्लास्टी से इलाज के दौरान सफलता की दर तकरीबन 80% -90%

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

बेहतर स्वास्थ्य से परे इंसानों को अपने जीवन में शरीर संबंधी कई छोटी-बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक ऐसी ही एक गंभीर समस्या है मूत्रमार्ग में असहज रूकावट, जो कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक देखी जाती है। पुरुषों में यूरेथ्रा (पेशाब नली) की लंबाई करीब 20 से.मी. जबकि महिलाओं में करीब 4 से.मी. होती है। मूत्रमार्ग में निहित पतली ट्यूब या नली की पेशाब को शरीर से बाहर करने में अहम् भूमिका होती है। जब सूजन, कमर की हड्डी में चोट (पेल्विक फ्रैक्चर), संक्रमण, केथेटर या फिर किसी ऑपरेशन या एक्सीडेंट के दौरान चोट लग जाती है, ये सभी कारण इस ट्यूब में पेशाब के प्रवाह को रोक देते हैं या धीमा कर देते हैं। चोट लगने या कूल्हे की हड्डी टूटने पर यूरेथ्रा डैमेज हो जाता है। परिणामस्वरूप, यह यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर डिसीज़ के रूप में पनपने लगता है। इसका इलाज सामान्य तौर पर देश के बड़े शहरों में ही उपलब्ध होता है, लेकिन इन सबसे परे इंदौर स्थित अग्रणी हॉस्पिटल 'मेदांता सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल' ने कुछ वर्षों पहले इस बीमारी से ग्रसित मरीजों को निजात दिलाने के लिए यूरेथ्रोप्लास्टी का जिम्मा बखूबी उठाया और हाल ही में विविध आयु वर्ग के मरीजों का 'बक्कल म्यूकोसल ग्राफ्ट यूरेथ्रोप्लास्टी' के जरिए सफलतापूर्वक इलाज किया है। उक्त बीमारी पर ज़ोर देते हुए डॉ. रवि नागर, एसोसिएट डायरेक्टर एवं

हेड, यूरोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट विभाग, मेदांता सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल, इंदौर कहते हैं, 'यूरेथ्रोप्लास्टी एक ऐसा रिकंस्ट्रक्टिव यूरोलॉजीकल सर्जिकल प्रोसीजर है, जिसमें विभिन्न स्ट्रिक्चर समस्याओं के इलाज के लिए मूत्रमार्ग का पुनर्निर्माण किया जाता है। यह मूत्रमार्ग के संकुचित हिस्से को हटाने या इसे बड़ा करने के लिए किया जाता है। यह बीमारी पुरुषों में यूरेथ्रा यानी पेशाब की नली में सिकुड़न की वजह से होती है, जिसके मुख्य कारण केथेटर, चोट, एसटीडी, इन्फेक्शन, यूरेथ्रा में त्वचा की कोई बीमारी आदि हो सकते हैं। स्ट्रिक्चर 2 से.मी. तक का होता है, तो दूरबीन से ऑपरेट किया जा सकता है, लेकिन इससे अधिक होने पर यूरेथ्रोप्लास्टी द्वारा इलाज को ही उपयुक्त माना जाता है। दूरबीन द्वारा सर्जरी करने के कारण कई बार इस बीमारी के दोबारा उभरने के आसार होते हैं, इसलिए ओपन सर्जरी को अधिक कारगर माना जाता है। इसके चलते ओरल कैविटी (मुँह) की अंदरूनी स्किन का ग्राफ्ट निकालकर प्लास्टिक सर्जरी की जाती है, जिसे सिकुड़न वाले हिस्से पर लगाया जाता है। यह सिकुड़न की समस्या से हमेशा के लिए निजात दिलाता है, और फिर भविष्य में यह कभी नहीं उभरती है।' मेदांता सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर डिसीज़ के इलाज के रूप में दूरबीन द्वारा ओआईयू, ओपन सर्जरी- एनास्ट्मोटिक यूरिथ्रोप्लास्टी, सब्स्टिट्यूशन यूरिथ्रोप्लास्टी, बक्कल म्यूकोसल ग्राफ्ट यूरेथ्रोप्लास्टी आदि की जाती है। विगत माह यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर डिसीज़ के चलते कई मरीजों की सफल सर्जरी की गई, जिनमें से एक मरीज युवा आयु वर्ग, अन्य 40-45 वर्ष और एक मरीज लगभग 80 वर्ष का है। सर्जरी का यह तरीका निश्चित तौर पर शहर और इसके आसपास के हर उम्र के मरीजों के लिए सार्थक उदाहरण के रूप में मिसाल कायम करेगा और उन्हें बेहतर जीवन स्तर प्रदान करेगा।

अदाणी ने किया मरीन सेवा प्रदाता कंपनी ओशन स्पार्कल का अधिग्रहण

ओशन स्पार्कल लिमिटेड भारत में प्रथम तथा विश्व में 11वें स्थान पर

अहमदाबाद। एजेंसी

अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड ('एपीएसइजेड') ने अपनी सहायक कंपनी, द अदाणी हार्बर सर्विसेज लिमिटेड ('टीएएचएसएल') के माध्यम से, भारत की अग्रणी थर्ड-पार्टी मरीन सर्विसेज प्रोवाइडर, ओशन स्पार्कल लिमिटेड ('ओएसएल') में 100 फीसदी हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए एक निश्चित समझौता किया है। कंपनी द्वारा की जाने वाली प्रमुख गतिविधियों में टोवेज, पाइलटेज और ड्रेजिंग शामिल हैं। अपने 94 स्वामित्व वाले जहाजों और 13 थर्ड-पार्टी स्वामित्व वाले जहाजों की परिसंपत्ति के साथ ओएसएल एक मार्केट लीडर है। ओएसएल के पास कंपनी में 300 करोड़ रुपये के फ्री कैश के साथ 1,700 करोड़ रुपये की एंटरप्राइज वैल्यू है। कंपनी की स्थापना 1995 में मरीन टेक्नोक्रेट्स के एक समूह द्वारा की गई थी, जिसमें श्री पी जयराज कुमार चेयरमैन और एमडी थे, जो ओएसएल बोर्ड के चेयरमैन के रूप में बने रहेंगे। एपीएसईजेड के सीईओ और पूर्णकालिक निदेशक, श्री करण अदाणी ने कहा' ओएसएल और अदाणी हार्बर सर्विसेज के तालमेल को देखते हुए, यह संगठित व्यवसाय बेहतर मार्जिन के साथ पांच वर्षों में दोगुना होने की संभावना है, जिससे एपीएसईजेड के शेयरधारकों के लिए आवश्यक महत्व पैदा होगा। यह अधिग्रहण न केवल एपीएसईजेड को भारत के मरीन सर्विस बाजार का एक जरुरी हिस्सा प्रदान करता है, बल्कि हमें अन्य देशों में अपनी मौजूदगी बनाने के लिए एक मंच भी देता है, जिससे एपीएसईजेड के सफर को सुविधाजनक रूप से 2030 तक विश्व स्तर पर सबसे बड़ा पोर्ट ऑपरेटर और भारत में सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट यूटिलिटी बनाया जा सके।' ओएसएल के अपने मौजूदा ग्राहकों के साथ लंबे समय के संबंध, जो 5 से 20 साल के अनुबंधों के तहत हैं (अनुबंधों का औसत समय- 7 वर्ष है)। इसके अलावा, यह कॉन्ट्रैक्ट टेकिंग और पे (टीओपीए) के आधार पर होते हैं, जिससे ओएसएल के बिजनेस मॉडल को मजबूती मिलती है। कंपनी की भारत के सभी प्रमुख पोर्ट्स, 15 छोटे पोर्ट्स और सभी 3 एलएनजी टर्मिनलों में उपस्थिति है। विगत वर्षों में, ओएसएल ने पूरे भारत में 1800 कर्मियों की एक टीम बनाई और कार्यरत की है। कंपनी को ओमान, सऊदी अरब, श्रीलंका, कतर, यमन और अफ्रीका में अपने संचालन के माध्यम से वैश्विक समुद्री सेवा में ख़ासा अनुभव प्राप्त है। ओएसएल का आकर्षक कैपिटल स्ट्रक्चर, क्वालिटी ऑपरेशंस और स्थायी कैश फ्लो, इसकी आकर्षक क्रेडिट रेटिंग (एए- आईसीआरए द्वारा) में रिफ्लेक्टेड होता है। वित्त वर्ष 22 में कंपनी को 600 करोड़ रुपये का रेवेनुए होने का अनुमान है जिसमें 310 करोड़ रुपये ईबीआइटीडीए और 135 करोड़ रुपये पीएटी से होने की उम्मीद है। ओएसएल के कुल राजस्व का लगभग 92% समुद्री सेवाओं (टोवेज और पाइलटेज) द्वारा योगदान दिया गया था, और शेष 8% ड्रेजिंग और अन्य अपतटीय सेवाओं के संयुक्त मिश्रण से प्राप्त होता है। ईबीआइटीडीए अनुपात का शुद्ध ऋण 1x से कम है। एपीएसईजेड द्वारा ओएसएल का अधिग्रहण 5.7x के आकर्षक ईवी/एफवाय23ई ईबीआईटीडीए पर संपन्न हुआ है। ऑपरेशनल और फाइनेंसियल तालमेल के दम पर, अदाणी हार्बर सर्विसेज का संयुक्त राजस्व और ईबीआईटीडीए, वित्त वर्ष 27 तक क्रमशः 100% उछलकर 5,000 करोड़ रुपये और 4,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है।

ओएनजीसी का नॉर्वे की कंपनी इक्विनॉर के साथ तेल एवं गैस खोज, स्वच्छ ऊर्जा के लिए करार

नयी दिल्ली। एजेंसी

सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) ने तेल एवं गैस खोज के साथ स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए नॉर्वे की ऊर्जा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी इक्विनॉर एएसए से करार किया है। कंपनी ने बुधवार को बयान में कहा कि इस सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर 26 अप्रैल को हस्ताक्षर किए गए। बयान में कहा गया है कि यह गठजोड़ खोज एवं उत्पादन, तेल एवं गैस के परिवहन और प्रसंस्करण एवं विपणन में सहयोग एवं भागीदारी के लिए है। इसके अलावा दोनों कंपनियां स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों पर भी मिलकर काम करेंगी। नॉर्वे की प्रमुख कंपनी इक्विनॉर की मौजूदगी करीब 30 देशों में है। नॉर्वे के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल की भारत यात्रा के दौरान इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस मौके पर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, नॉर्वे की विदेश मंत्री एन्निकेन ह्यूटफेल्ट और ओएनजीसी की चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक अल्का मित्तल मौजूद थीं।

कोरोना के बदल रहे लक्षण, संक्रमितों की बढ़ती संख्या में क्या फिर से लग सकता लॉकडाउन

लखनऊ। एजेंसी

कोरोना वायरस ने न केवल देश बल्कि उत्तर प्रदेश की भी चिंता बढ़ा दी है। पिछले कुछ दिनों से देश में नए मामलों की संख्या दो हजार से ज्यादा आ रही है। जबकि प्रदेश में रोजमा 100-150 मरीज संक्रमित हो रहे। इसे कोरोना की चौथी लहर के रूप में देखा जा रहा है। यूरोप और एशिया के कई देशों में कोरोना ने पहले से ही तबाही मचाई हुई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक करेंगे। लॉकडाउन लगेगा या नहीं इस पर भी चर्चा की जाएगी। प्रदेश में वर्तमान में कुल एक्टिव केस की संख्या 1277 हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) ने चेतावनी दी है कि भारत में ओमीक्रोन बीए.2 (Omicron BA.2) वेरिएंट के मामले बढ़ रहे हैं। इस वेरिएंट में मूल ओमीक्रोन से ज्यादा तेजी से फैलने की क्षमता है। चिंता की बात यह है कि कोरोना के कुछ लक्षण भी बदले हैं। अब सिर्फ बुखार, खांसी या जुकाम आदि कोरोना के लक्षण नहीं रह गए हैं। वैज्ञानिकों और त्वचा विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना त्वचा को प्रभावित कर सकता है, जिससे त्वचा से जुड़े कई लक्षण महसूस हो सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कोरोना वायरस ह्यूमन एंडोथेलियल सेल्स को संक्रमित कर सकता है, जिससे त्वचा में सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो सकता है, जिससे त्वचा की समस्याएं हो सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इसमें स्कूल, बाजारों की पाबंदियां और भीड़-भाड़ को लेकर निर्णय लिया जा सकता है। हालांकि अधिकारियों का कहना है अभी लॉकडाउन जैसी स्थितियां नहीं है। भीड़-भाड़ रोकने के लिए मास्टर प्लान तैयार हो रहा है।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।